सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 260, नई दिल्ली । शनिवार, 30 नवम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

यह मत मानिए कि जीत ही सब कुछ है, महत्वपूर्ण यह है कि आप किस उद्देश्य के लिए जीतना चाहते हैं...

03 विधानसभा में कैग रिपोर्ट हो पेश', उपराज्यपाल ने फिर लिखा CM को पत्र
06 पंजाब मे गणित विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता
08 38% महिलाएं बनीं सिविल सेवा अधिकारियों का हिस्सा: अमित शाह

प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर परिवहन निगमों की बसों पर दिल्ली में अनुमति पर रोक और प्राइवेट स्वामियों की बसों को अनुमति, क्या परिवहन आयुक्त दिल्ली द्वारा जारी आदेश सही और न्यायसंगत है ?

संजय बाटला

नई दिल्ली। उत्तराखंड परिवहन निगम के महाप्रबंधक (संचालन) द्वारा 27 नवम्बर 2024 को निदेशक तकनीकी सीक्यूएम और विशेष आयुक्त परिवहन दिल्ली को पत्र लिखकर उठाया महत्वपूर्ण मुद्दा और दिल्ली में उत्तराखंड परिवहन निगम की डीजल मानक IV बसों की मांगी उसी तर्ज पर अनुमति

उपरोक्त मुद्दे पर उत्तराखंड परिवहन निगम के महाप्रबंधक संचालन पवन मेहरा द्वारा जो तर्क दिए गए हैं वह बहुत ही तर्कसंगत और न्यायिक है और सिद्ध करता हैं की दिल्ली परिवहन विभाग के आला अधिकारी और निदेशक तकनीकी सीक्यूएम दिल्ली में प्रदुषण पर नियंत्रण के उदेश्य से अधिक प्राइवेट बड़े वाहन ऑपरेटर्स के हित को ध्यान में रखकर आदेश जारी किया गया है।

दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 15-11-2024 में वर्णित बिंदु -04 में उल्लेखित किया गया है कि ईवी/सीएनजी/बीएस VI डीजल के अलावा एनसीआर राज्यों से आने वाली अंतरराज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है (आल इंडिया टूरिस्ट परमिट के साथ संचालित बसों/ टेंपो ट्रेवलर को छोड़कर) उक्त आदेश से स्पष्ट है कि आल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर संचालित डीजल बस स्वामी किसी भी मानक चाहे वह यूरो III हो या यूरो IV या यूरो VI को दिल्ली में प्रवेश कर सकता है।

जाने क्या लिखा अपने पत्र के माध्यम से उत्तराखंड महाप्रबंधक ने,

उत्तराखण्ड परिवहन निगम, पत्रांक 529 / एचक्यू/संचालन- 11/2023, दिनांक 27 नवंबर 2024

सेवा में,

1. निदेशक तकनीकी सीएक्यूएम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। 17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एसटीसी बिल्डिंग), टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली 110001

एससीओटी (4) टीपीटी 64953 सभी/2024/ दिनांक 29/11/24

2. विशेष आयुक्त (परिवहन) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 5/9, अंडर हिल रोड, दिल्ली 110054

विषयः- दिल्ली-एनसीआर में संशोधित जीआरएपी के चरण-IV (गंभीर वायु गुणवत्ता) के अंतर्गत कार्रवाई का कार्यान्वयन - उठाए जाने वाले कदम।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश संख्या / दिनांक 15-11-2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र में वर्णित बिन्दु -04 में उल्लेख किया गया है कि ईवी/सीएनजी /बीएस VI डीजल के अलावा एनसीआर राज्यों से आने वाली अन्तराज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है (ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के साथ संचालित बसों /टेपों ट्रैवलर को छोड़कर)₹

उक्त आदेश से स्पष्ट है कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर बस संचालक/स्वामी किसी भी प्रकार की बस लेकर दिल्ली में प्रवेश कर सकता है।

महोदय उपरोक्त आदेश के द्वारा ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट से सम्बन्धित बसों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है तथा वर्तमान में उक्त परमिटों पर कई निजी संचालकों / कम्पनी की बीएस IV मॉडल की डीजल बसें दिल्ली में आई०एस०बी०टी०, कश्मीरी गेट / आनन्द विहार व अन्य स्थानों से संचालित हो रही है, किन्तु उत्तराखण्ड परिवहन निगम की अन्तर्राज्यीय बसों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगायी गई है, जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस संचालक / स्वामी की भांति उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बीएस IV मॉडल की डीजल बसों को भी अनुमति प्रदान की जाय अथवा ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर बस संचालक/स्वामियों की बीएस IV, III मॉडल की डीजल बसों का आई०एस०बी०टी०, कश्मीरी गेट / आनन्द विहार दिल्ली से बस संचालन पर भी तत्काल रोक लगायी जाय।

भवदीय

(पवन मेहरा) महाप्रबन्धक (संचालन) निगम मुख्यालय

उपरोक्त आदेश को अब आप ही सोचे समझे की दिल्ली परिवहन आयुक्त तकनीकी निदेशक सीक्यूएम को साथ मिलाकर जो प्रदुषण नियंत्रण के उदेश्य से कर रहा है क्या वह आम जनता के हित में है और प्रदुषण नियंत्रण के प्रति सही सख्त आदेश था या प्रदुषण नियंत्रण के नाम पर आल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर संचालित डीजल बस स्वामियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से था।

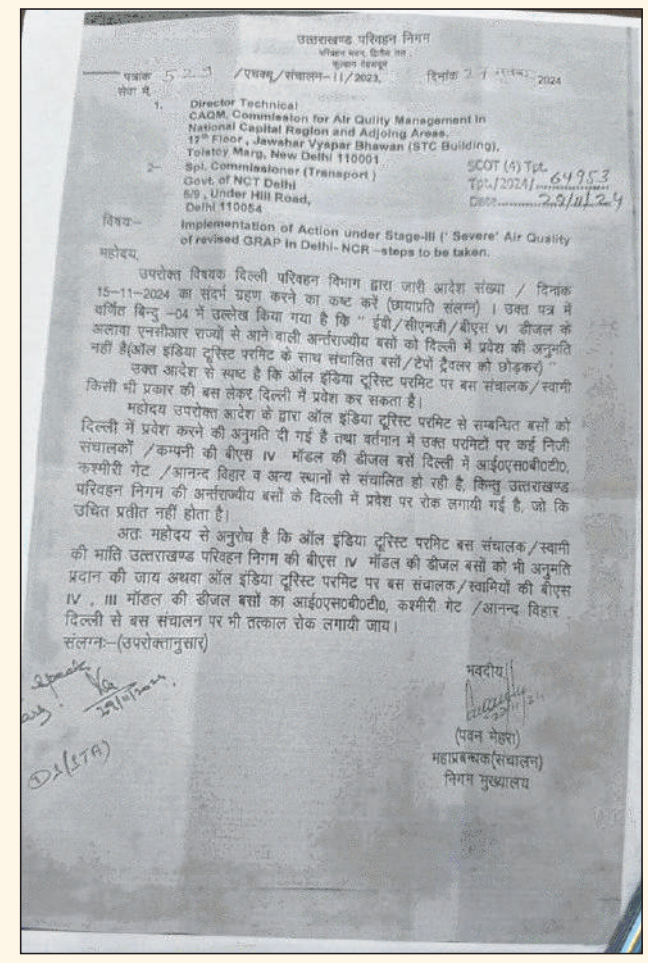

अगर रोक लगानी आवश्यक है तो बसे निगम की हो या प्राईवेट स्वामी की रोक लगानी चाहिए पर एक पर रोक और दूसरे को खुली छूट तो क्या प्रदुषण नियंत्रित हो पाएगा, बड़ा सवाल ?

उत्तराखण्ड परिवहन निगम

पत्रांक 529 /एचक्यू/संचालन–11/2023, दिनांक 27 नवम्बर 2024

सेवा में,

1. Director Technical
CAQM, Commission for Air Qulity Management in National Capital Region and Adjoing Areas.
17th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan (STC Building), Tolstoy Marg, New Delhi 110001

2- Spl. Commissioner (Transport)
Govt. of NCT Delhi
5/9, Under Hill Road,
Delhi 110054

SCOT (4) Tpt.
Tpt./2024/ 64953
Date 29/11/24

विषय– Implementation of Action under Stage-III ('Severe' Air Quality of revised GRAP in Delhi-NCR –steps to be taken.

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश संख्या / दिनांक 15–11–2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त पत्र में वर्णित बिन्दु –04 में उल्लेख किया गया है कि " ईवी/सीएनजी/बीएस VI डीजल के अलावा एनसीआर राज्यों से आने वाली अन्तर्राज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है(ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के साथ संचालित बसों/टेंपो ट्रैवलर को छोड़कर) "

उक्त आदेश से स्पष्ट है कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर बस संचालक/स्वामी किसी भी प्रकार की बस लेकर दिल्ली में प्रवेश कर सकता है।

महोदय उपरोक्त आदेश के द्वारा ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट से सम्बन्धित बसों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है तथा वर्तमान में उक्त परमिटों पर कई निजी संचालकों /कम्पनी की बीएस IV मॉडल की डीजल बसें दिल्ली में आई0एस0बी0टी0, कश्मीरी गेट /आनन्द विहार व अन्य स्थानों से संचालित हो रही है, किन्तु उत्तराखण्ड परिवहन निगम की अन्तर्राज्यीय बसों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगायी गई है, जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस संचालक/स्वामी की भांति उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बीएस IV मॉडल की डीजल बसों को भी अनुमति प्रदान की जाय अथवा ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर बस संचालक/स्वामियों की बीएस IV, III मॉडल की डीजल बसों का आई0एस0बी0टी0, कश्मीरी गेट /आनन्द विहार दिल्ली से बस संचालन पर भी तत्काल रोक लगायी जाय।

संलग्नः–(उपरोक्तानुसार)

भवदीय
(पवन मेहरा)
महाप्रबन्धक(संचालन)
निगम मुख्यालय

नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर घटाई गई स्पीड लिमिट, 4000 रुपये तक का कटेगा चालान

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। 15 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक इन दोनों एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चलाने की गति सीमा में बदलाव किया गया है। यह नियम हल्के और भारी वाहनों के लिए अलग-अलग लागू होंगे।

स्पीड लिमिट में बदलाव

1. यमुना एक्सप्रेसवे पर

- हल्के वाहनों के लिए स्पीड लिमिट को 100 kmph से घटाकर 75 kmph किया गया है।
- भारी वाहनों के लिए स्पीड लिमिट 80 kmph से घटाकर 60 kmph कर दी गई है।

2. नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर

- हल्के वाहनों के लिए स्पीड लिमिट को 100 kmph से घटाकर 75 kmph किया गया है।
- भारी वाहनों के लिए स्पीड लिमिट 60 kmph से घटाकर 50 kmph कर दी गई है।

जुर्माना

जो वाहन चालक स्पीड लिमिट से अधिक तेज़ गति से वाहन चलाएंगे, उन पर जुर्माना लगाया जाएगाः

- हल्के वाहनों पर 2000 रुपये का जुर्माना
- भारी वाहनों पर 4000 रुपये का जुर्माना

यह जुर्माना 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक लागू रहेगा, और यह नियम दोनों एक्सप्रेसवे पर लागू होगा।

प्रदूषण के ख़तरों से कैसे बचें? जानिए डॉक्टरों के सुझाव

इशिका मुख्य रिपोर्टर रांची झारखंड

आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में, सांस लेने की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। हवा में मौजूद प्रदूषण हमारे फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुँचा सकता है, और इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, और पहले से फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे लोगों पर।

हवा में मौजूद पीएम 2.5 जैसे छोटे-छोटे कण, जो वाहन उत्सर्जन, फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं, और जंगल की आग से पैदा होते हैं, हमारे फेफड़ों के अंदर तक जा सकते हैं। यह न सिर्फ साँस की दिक्कतें बढ़ाते हैं, बल्कि फेफड़ों के कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों का ख़तरा भी पैदा करते हैं।

डॉक्टर प्रभु प्रसाद मणिपाल हॉस्पिटल गोवा :- प्रदूषण का असर हर व्यक्ति पर अलग-अलग हो सकता है। बच्चों और बुजुर्गों के साथ-साथ उन लोगों पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, जिनकी शारीरिक क्षमता पहले से कमजोर है। नाक बंद होना, साँस लेने में दिक्कत, लगातार खांसी, और अस्थमा का बढ़ना आम समस्याएँ बनती जा रही हैं।

लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। सही कदम उठाकर आप अपने और अपने परिवार के फेफड़ों को सुरक्षित रख सकते हैं। आइए जानते हैं, कैसे।

1. वायु गुणवत्ता की जांच करें :- हर दिन की शुरुआत स्थानीय एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) जांचने से करें। अगर हवा खराब हो, तो बाहर जाने से बचें।

2. भीड़भाड़ वाले रास्तों से बचें:- सर्दियों में भारी ट्रैफिक वाले इलाकों में पैदल चलने से बचें। गर्मियों में दोपहर के समय प्रदूषण ज़्यादा होता है, इसलिए सुबह-सवेरे बाहर जाएं।₹

3. वैकल्पिक परिवहन का इस्तेमाल करें:- गाड़ी चलाने से पहले सोचें। पैदल चलना, साइकिलिंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इससे ना सिर्फ प्रदूषण घटेगा, बल्कि आपकी सेहत भी सुधरेगी।

4. गाड़ियों का सही रखरखाव करें:- कारपूलिंग करें, गाड़ी स्टार्ट रहने पर इंजन बंद करें, और अपने वाहन की समय पर सर्विसिंग करवाएं।

5. ऊर्जा की बचत और स्वच्छ ऊर्जा अपनाएं:- अपने घर में ऊर्जा की खपत कम करें या रिन्युएबल एनर्जी का इस्तेमाल करें। कूड़ा-कचरा या लकड़ी जलाने से बचें।

प्रदूषण से बचाव के ये छोटे-छोटे कदम न केवल आपके फेफड़ों को स्वस्थ रखेंगे, बल्कि आपके आस-पास की हवा को भी साफ बनाएंगे।

तो आइए, मिलकर एक स्वस्थ भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अपनी सेहत का ख्याल रखें और दूसरों को भी जागरूक करें।

दिल्ली परिवहन विभाग की आई.टी. शाखा का जादू दुनियां में सबसे निराला

संजय बाटला

नई दिल्ली। आपकी जानकारी हेतु बता दें दिल्ली परिवहन विभाग की आई.टी शाखा जो करके दिखा सकती हैं वह दुनियां का बड़े से बड़ा जादूगर भी करके नहीं दिखा सकता,

कारण आज की तारीख़ में दिल्ली आई.टी शाखा के सर्वोत्तम पद पर स्वयं परिवहन आयुक्त कार्यरत है और उनकी कृपा दृष्टि आई.टी शाखा के अधिकारियों पर बनी रहना स्वाभाविक है।

**किसी वाहन की फिटनेस हो जाने के बाद भी वाहन मालिक को अगले कार्य करने के लिए आनलाइन आवेदन पर प्रयोग की जा चुकी फिटनेस फीस पेंडिंग दिखाकर काम नहीं करने देना,

**वाहन की इंश्योरेंस होते हुए भी बिना इंश्योरेंस वाहन को दिखा देना

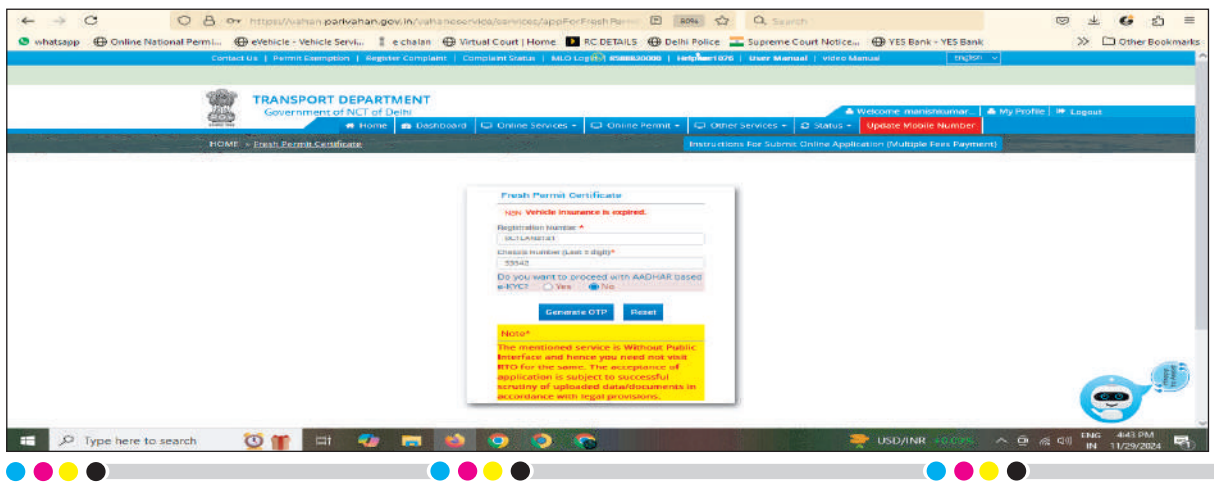

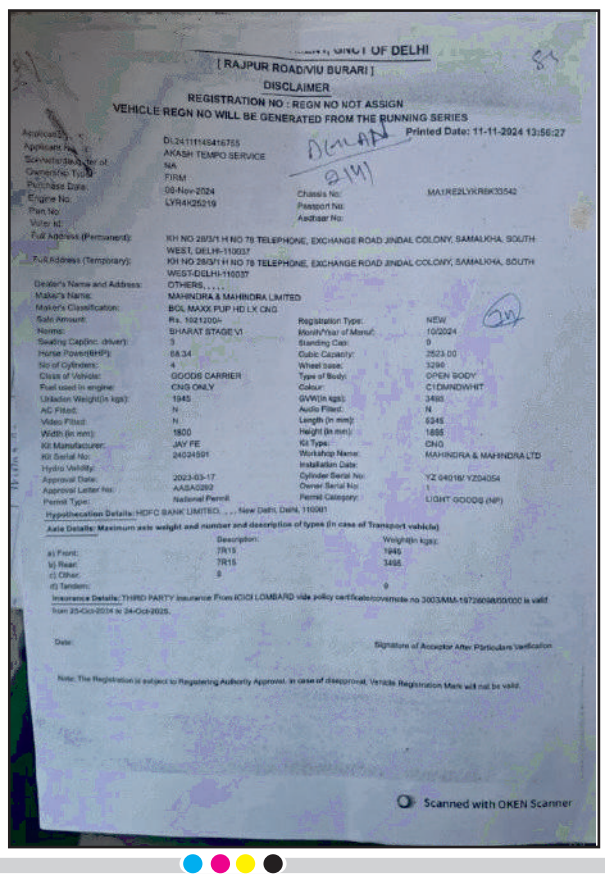

**वाहन के लिए प्रयोग होने वाले किसी श्रेणी के परमिट के जमा हो जाने के बाद दूसरी श्रेणी सम्बन्धित फिटनेस और वाहन प्रमाण पत्र में श्रेणी बदलाव के बावजूद नई श्रेणी के लिए परमिट आवेदन नहीं करने देना

**नए पंजीकरण होने वाले वाहनों के पंजीकरण पर बिना इंश्योरेंस दिखाकर पंजीकरण नहीं होने देना

**वाहन मालिकों द्वारा अपने वाहनों में पहले से लगे वीएलटीडी डिवाइस की जगह अन्य किसी कम्पनी का वीएलटीडी डिवाइस लगवाने पर किसी को दो मिनट में अनुमति और किसी को धक्के/ चक्कर लगाने पर भी कई दिनो तक रोके रखना

**किसी भी समय आनलाइन आवेदन सेवा को रोक देना जैसे महत्वपूर्ण जादू करते रहना दिल्ली परिवहन विभाग की आई.टी शाखा का प्रतिदिन का काम है।

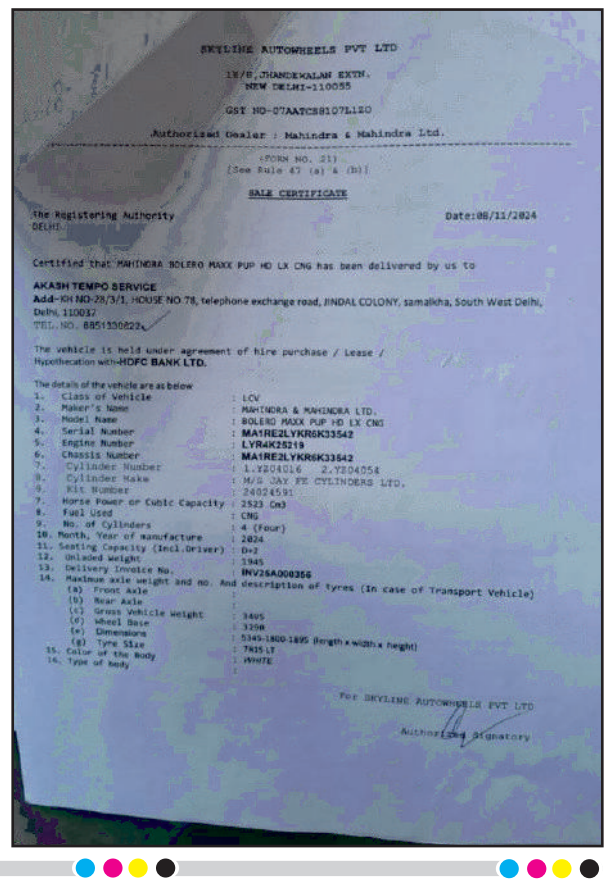

अब आप ही सोचे की इस तरह के जादू करने वाली शाखा और उस शाखा के प्रबंधक के सिर पर हो आला अधिकारी का हाथ तो कितना सुखद होगा दिल्ली कि जनता के लिए आनलाइन फेंस फ्री आवेदन प्रक्रिया

भगवान श्रीराम के पदचिन्हों पर चल रहे हैं योगी आदित्यनाथ

महाराष्ट्र चुनाव को बीजेपी ने विशाल बहुमत से जीता,इस जीत का सबसे ज्यादा श्रेय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी दिया जा रहा है,यदि यही सच है तो योगी भगवान श्री राम के बाद दूसरे उत्तर भारतीय हैं जिन्होंने दक्षिण को जीता है वरना कोई भी उत्तर भारतीय शासक महाराष्ट्र की दीवार तोड़ नहीं पाया। आखिर योगी यह इतिहास रचने में क्यों और कैसे सफल हुए इसकी चर्चा करते हैं।

असल में योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ महाराष्ट्र नहीं जिताया बल्कि इसके पहले हरियाणा में भी हारी हुई बाजी को योगी ने ही पलटा था और उसके भी पहले वे उत्तर प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री बने जिन्होंने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की हो। यूपी की डबल जीत आजाद भारत का एक इतिहास है। आखिर योगी आदित्यनाथ में ऐसा क्या है कि जहां जाते हैं वहां से जीतकर ही लौटते हैं,इसका सही जवाब यह है कि योगीजी भगवान श्रीराम के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। उनमें वो सारे गुण हैं जो श्री राम के अनुसार एक व्यक्ति में होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के आदर्श राम हैं इसलिए योगी अजेय हैं।

महाभारत में शकुनि एक बार कहते हैं कि₹ योद्धा और महायोद्धा को युद्ध से जीता जा सकता है लेकिन जो सर्व शक्तिमान होता है उसको सिर्फ धर्म से ही जीता जा सकता है।₹ श्रीराम के जीवन में धर्म ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है यही कारण है कि वो त्रिलोक विजेता रावण को हरा सके। रावण को युद्ध में कोई नहीं हरा सकता था लेकिन सत्य और धर्म के आगे रावण विवश हो गया। रावण कितना विवश हो गया होगा इसका अंदाज इस बात से लगा सकते हैं कि लंका की जनता भी श्री राम की महानता का गुणगान करती थी। राजतंत्र में भी जनता जिसका गुणगान करे वही विजेता बनता है फिर आज तो प्रजातंत्र है,यहां तो जनता ही सब कुछ है । आज जो जनता का भरोसा जीत लेता है वही चुनाव जीत लेता है । योगी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वे जनता का भरोसा जीत चुके हैं और जनता का भरोसा उन्होंने ताकत ,पैसे या पुलिस की दम पर नहीं जीता है बल्कि नैतिकता और ईमानदारी के दम पर जीता है ,यही कारण है कि योगी जी के मुंह से निकला एक एक वाक्य जनता के लिए ब्रह्म वाक्य हो जाता है और वह इस पर आंख मूंदकर भरोसा कर लेती है । योगीजी ने अपनी ईमानदारी साबित की है, देशभक्ति साबित की है और अपनी रामभक्ति साबित की है,जबकि अन्य नेता कहीं न कहीं इस मामले में योगी जी से पीछे हैं यहां तक कि उनकी खुद की पार्टी के बड़े बड़े नेता भी योगी जी जितने भरोसेमंद नहीं लगते फिर विपक्ष की तो बात ही क्या करना।

तो आते हैं महाराष्ट्र ,यहां महा विकास अघाड़ी के नेताओं ने बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं पर बड़े बड़े आरोप लगाए लेकिन अकेले योगी ऐसे नेता थे जिनके ऊपर कोई आरोप ही नहीं लग सकता था। यही कारण है कि संजय राउत जैसे बड़बोले नेता भी योगीजी के बारे में सिर्फ इतना ही कह सके कि ₹अपने बाबाजी हैं।₹ संजय राउत तो मोदीजी पर भी बड़े बड़े आरोप लगाते रहे हैं लेकिन योगी का सामना करने की हिम्मत उनकी भी नहीं हुई । वे भी योगी पर ऐसा कोई आरोप लगा नहीं सकते जिस पर जनता यकीन करे क्योंकि भ्रष्ट वे हैं नहीं, सिर्फ चुनावी हिंदू वे हैं नहीं, कैरेक्टर में कोई लोचा है नहीं और उनके लॉ एंड ऑर्डर में कोई लूस पोल है नहीं,कोई क्रिमिनल केस उन पर है नहीं,झूठ वो आज तक बोले नहीं,छुपाकर कोई काम करते नहीं । जो करते हैं डंके की चोट पर करते हैं,एक बात के धनी हैं। यही सारे गुण श्री राम में थे जिनका वर्णन हनुमान जी ने सीता जी से तब किया था जब अशोक वाटिका में सीता जी हनुमान से श्रीराम के गुण अवगुण पूछती हैं। तब हनुमान जी श्रीराम के गुण इस प्रकार बताते हैं कि श्रीराम ईमानदार, चरित्रवान, सत्यनिष्ठ, एक ही तरह की बात कहने वाले, एक मार्ग पर चलने वाले, युद्ध में शेर की भांति बर्ताव करने वाले, युद्धनीति में निपुण और धर्म शास्त्रों के ज्ञाता,कला पारखी,सन्यासी जीवन जीने वाले और शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। यह गुण श्री राम में थे,अब हम यदि गंभीरता से सोचें तो लगभग यही सब गुण हमें योगी आदित्यनाथ में दिखाई नहीं देते क्या ? लगभग यही सारे गुण योगीजी में भी हैं इसलिए उन्हें श्रीराम के पदचिन्हों पर चलने वाला योद्धा कहा जाए तो अतिश्योक्ति नहीं होगी । नियति भी योगी के साथ है तभी तो योगीजी अभी तक अजेय भी साबित हुए हैं । अन्य विपक्षियों से योगी जी के गुणों की तुलना करें तो उनमें अकेले में ही वो गुण हैं जो सारे विपक्षियों पर भारी पड़ सकें क्योंकि ईमानदारी के मामले में योगीजी शरद पंवार से कहीं अधिक बेहतर हैं, तो नीति निपुणता में कांग्रेस से बेहतर हैं और धर्मनिष्ठा में उद्धव से बेहतर हैं इसलिए जितनी जनता पूरे विपक्ष पर भरोसा करती उससे ज्यादा अकेले योगी पर करने लगी,इस बात का सबूत है उनकी सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ । जिसमें सभी वर्ग के लोग शामिल होते थे और खासकर महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में आती थीं । आज महिलाएं ही सबसे सशक्त वोट बैंक हैं । आज महिलाएं भी एकतरफा वोट करती हैं इसलिए किसी की सत्ता बनाना या उखाड़ना अब महिलाओं के हाथ में है । यही कारण है कि जो महिलाओं में पॉपुलर होता है आजकल वही विजेता होता है। ऐसा ही नजारा लंका में था जब वहां के पुरुष श्रीराम के विरुद्ध लड़ रहे थे लेकिन वहां की महिलाएं श्रीराम का गुणगान करती थीं । खासकर जब श्री राम ने मेघनाद का शव सम्मानपूर्वक लंका में पहुंचाया तब लंका की साधारण महिलाएं भी श्री राम को एक भला आदमी बताने लगी थीं और जब श्री राम युद्धभूमि में मंदोदरी का सम्मान करते हैं तब राजपरिवार की महिलाएं भी श्री राम की उपासक बन जाती हैं।श्री राम लंका की महिलाओं के मन में यह बात बैठाने में सफल होते हैं कि रावण महिलाओं की इज्जत नहीं करता था इसलिए उसका वध किया,यही बात योगीजी ने भी साबित की है कि उनका बुलडोजर सिर्फ अपराधियों के घर तोड़ता है आम लोगों के नहीं। योगी जी ने ऑपरेशन मजनू शुरू किया तो महिलाएं सुरक्षित महसूस करने लगीं और इसका असर सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि पूरे देश में हुआ ,महाराष्ट्र में भी यही देखने को मिला। महिलाएं भले ही बीजेपी के अन्य नेताओं के खिलाफ बोली भी हों लेकिन कोई भी महिला योगी जी के खिलाफ बोलती हुई नहीं दिखी इसीलिए योगीजी ने जब महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े किए तो महिलाओं ने पूरी तरह योगी का समर्थन किया। इसलिए बाबाजी ने आखिरी के सिर्फ तीन दिनों में ही एकतरफा जीत की कहानी लिख दी और परिणाम एकतरफा आए। आज महाराष्ट्र की जीत पर कई तरह की टीका टिप्पणी हो रही हैं । ईवीएम को भी क्रेडिट दिया जा रहा है लेकिन इस जीत को हरियाणा और यूपी की जीत से जोड़कर देखा जाये तो यह जीत नैतिकता और सुशासन की जीत प्रतीत होती है । जैसा कि गीता के आखिर में संजय कहते हैं कि जहां धर्म है वहां श्रीकृष्ण हैं और जहां श्रीकृष्ण हैं वहां विजय है। सच बात तो यह है कि नेताओं को एक दूसरे की आलोचना करने के बजाए योगीजी के रास्ते पर चलना चाहिए,जो नेता योगीजी जैसे नैतिक ईमानदार, चरित्रवान, राष्ट्रभक्त और रामभक्त होंगे विजय भी उनको ही मिलेगी क्योंकि जनता हमेशा बेहतर भविष्य का चुनाव करती है अतीत का नहीं। आज योगी आदित्यनाथ में भी भारत का भविष्य देखा जा रहा है,इसलिए उनको इतना समर्थन हासिल हो रहा है।

रेडमी के80 के इस फोन की बढ़ी सेल, जानें गजब के फीचर्स और कीमत

रेडमी K80 और K80 प्रो ने हाल ही चीन में अपनी K सीरीज के तहत दो स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया है। ये फोन Redmi K80 और Redmi K80 Pro है। कल इस फोन इन दोनों फोन को चीन में पहली बार सेल के लिए उपलब्ध कराया गया। इस सेल के लाइव होते ही फोन को जबरदस्त रिस्पांस मिला।

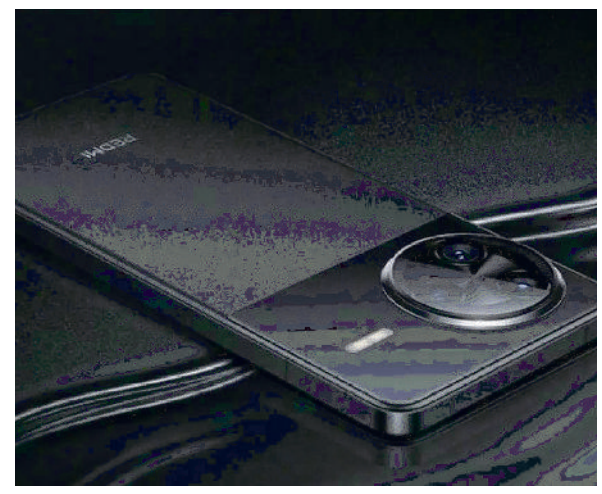

Redmi ने हाल ही चीन में अपनी K सीरीज के तहत दो स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया है। ये फोन Redmi K80 और Redmi K80 Pro है। कल इस फोन इन दोनों फोन को चीन में पहली बार सेल के लिए उपलब्ध कराया गया। इस सेल के लाइव होते ही फोन को जबरदस्त रिस्पांस मिला।

रेडमी ने 27 नवंबर को K80 और K80 प्रो फोन लॉन्च किए। अब Xiaomi ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि Redmi K80 और K80 Pro की सेल में रिकॉर्डतोड़ सेल की है। कंपनी ने खुद जानकारी दी है। कंपनी ने खुद जानकारी दी है कि एक दिन में 660,600 से ज्यादा फोन बिक चुके हैं।

दोनों ही फोन्स को 5 वैरिएंट्स में पेश किया गया है। रेडमी K80 के बेस 12GB + 256GB वैरिएंट की कीमत 2499 यूआन लगभग 29,170 रुपये है। तो वहीं रेडमी K80 Pro के 12GB +256GB वर्जन की कीमत 3699 युआन लगभग 43,180 रुपये है। दोनों ही फोन्स को Snow Rock White, Mountain Green और Mysterious Night Black इन तीन रंगों में पेश किया गया है।

इस फोन में 6.67 इंच का 2K रिजोल्यूशन है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में Snapdragon 8Gen मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा है। फ्रंचा में 20 मेगापिक्सल OmniVision सेल्फी कैमरा मिल जाता है। रेडमी का ये फोन 6550mAh बैटरी के साथ आता है।

फीचर्स और स्पेस

प्रो वैरिएंट Dnapdragon 8 Elite 3nm चिपसेट के साथ आता है। इस्मने 6000mAh बैटरी है जो 120W वायर्ड और 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बेस और प्रो वैरिएंट के कैमरा सेम है बस प्रो में 32MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा जो बेस में 8MP का है।

सर्दियों में बना रहे साउथ इंडिया घूमने का प्लान तो इन ट्रैवल टिप्स को फॉलो कर शानदार बनाएं अपनी यात्रा

अगर आप भी सर्दियों में दक्षिण भारत घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसे ट्रैवल टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको फॉलो कर आप अपनी यात्रा को अधिक यादगार बना सकते हैं।

दक्षिण भारत देश का एक प्रमुख और बेहद खूबसूरत हिस्सा है। इस हिस्से में समुद्री तटों से लेकर पहाड़ी इलाकों में घूमने का अपना ही मजा होता है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों की खूबसूरती देश भर में फेमस है। न सिर्फ देश बल्कि विदेश से भी लोग यहां पर घूमने के लिए और मौज-मस्ती के लिए पहुंचते हैं। बता दें कि दक्षिण भारतीय हिस्से को विश्व में एक फेमस पर्यटन केंद्र माना जाता है। लेकिन इस हिस्से में घूमने का मजा तभी आता है, जब आप इसको करीब से जानते हैं। ऐसे में अगर आप भी सर्दियों में दक्षिण भारत घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसे ट्रैवल टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको फॉलो कर आप अपनी यात्रा को अधिक यादगार बना सकते हैं।

मौसम पर रखें नजर

अगर आप साउथ इंडिया की किसी भी जगह घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको वहां के मौसम के बारे में पहले जरूर मालूम करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि अन्य जगहों की तरह कुर्ग, मुन्नार, ऊटी और गोकर्ण में ठंड पड़ रही होगी, तो आप गलत भी हो सकते हैं। इसलिए आपको घूमने निकलने से पहले मौसम का जरूर ध्यान रखना चाहिए।

जरूरत के मुताबिक पैक करें कपड़े

सर्दियों में आप जिस भी जगह घूमने जा रहे हैं, वहां पर उस जगह के मौसम के हिसाब से जानकारी प्राप्त करने के बाद उसी के हिसाब से कपड़े पैक करें। अगर गर्मी लगे तो आप पतले कपड़े भी पैक कर सकते हैं। वहीं अगर जहां आप जा रहे हैं, वहां सिर्फ सुबह और रात में ठंड पड़ रही है, तो आप एक दो ऊनी कपड़े पैक कर सकते हैं। इससे आपका सफर भी अच्छा होगा और ज्यादा सामान भी नहीं होगा।

ट्रैफिक का रखें ध्यान

देश के अन्य हिस्सों की तरह ही साउथ इंडिया में भी खूब ट्रैफिक होता है। अगर आप पहली बार यहां घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको पहले से तैयार रहना चाहिए।

बता दें कि देश के अन्य हिस्सों में जब कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो दक्षिण भारत की कुछ जगहों पर मौसम गर्म रहता है। इसलिए पर्यटक गर्मी के एहसास के लिए दक्षिण भारत घूमने के लिए निकलते हैं। जब भारी संख्या पर्यटक घूमने के लिए निकलते हैं, तो फेमस जगहों पर खूब ट्रैफिक रहता है।

खानपान

अगर आप सर्दियों में पहली बार दक्षिण भारत की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो यहां पर यात्रा के दौरान अपने खानपान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो यहां के व्यंजन काफी टेस्टी होते हैं। लेकिन कुछ लोगों को यहां का खाना पसंद नहीं होता है।

सर्दी के मौसम में दक्षिण भारतीय लोग इडली सांबर, मेदु वड़ा, उत्तपम और डोसा आदि खाना खूब पसंद करते हैं। अगर आपको भी सर्दियों में यह खाना पसंद है, तो आपके घूमने का मजा दोगुना हो जाएगा। आप दक्षिण भारत में जिस जगह पर घूमने जा रहे हैं, वहां पर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट इंडियन रेस्त्रां के बारे में पता कर सकते हैं।

सर्दियों में खोए नूर को ऐसे पाएं वापस, खिल उठेगा चेहरा

सर्दियों में हमारी स्किन को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। वहीं जब स्किन का सही से ध्यान नहीं रखा जाता है, तो इसका निखार खोने लगता है। ऐसे में आप कुछ टिप्स अपनाकर घर पर पार्लर जैसा निखार पा सकती हैं।

सर्दियों में हमारी स्किन को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। वहीं जब स्किन का सही से ध्यान नहीं रखा जाता है, तो इसका निखार खोने लगता है और चेहरा डल पड़ने लगता है। हम सभी सर्दियों में फेस को मॉइश्चराइज करने के लिए कोल्ड क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इससे चेहरे का रूखापन भले ही थोड़ी देर के लिए चला जाता है, लेकिन साथ ही चेहरे का निखार भी जाने लगता है। अगर सर्दियों में आपके चेहरे का नूर भी खो जाता है, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आप घर पर ही पार्लर जैसा निखार पा सकते हैं।

शहद

फेस पर शहद लगाने से आपका खोया हुआ निखार वापस आ सकता है। वहीं सर्दी के मौसम में चेहरे को मॉइश्चराइज करने का यह एक अच्छा घरेलू तरीका भी माना जाता है। शहद की मदद से आप अपने चेहरे की खोई हुई रंगत को भी वापस पा सकती हैं। साथ ही चेहरे पर होने वाले दाग-धब्बों और झुर्रियों को भी यह गायब करने का एक अच्छा ऑप्शन है।

बेसन

बता दें कि त्वचा के लिए बेसन एक अच्छा घरेलू तरीका माना जाता है। इससे आप घर पर ही पार्लर जैसा निखार पा सकते हैं। चेहरे पर बेसन और हल्दी में कच्चा दूध मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। फिर इसको फेस पर अप्लाई करें और 15 मिनट तक सूखने दें। अब पानी से फेसवॉश कर लें। इससे फेसपैक से आप अपनी त्वचा में खुद बदलाव देख सकेंगी। एक्सपर्ट की मानें, तो बेसन और हल्दी का पेस्ट स्किन के लिए काफी अच्छा होता है।

नींबू

फेस के रूखेपन को दूर करने और खोए हुए निखार को वापस पाने के लिए आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। क्योंकि नींबू विटामिन सी से भरपूर होता है और यह स्किन के लिए भी काफी गुणकारी माना जाता है। आप अपने चेहरे पर नींबू की सहायता से निखार पा सकते हैं।

पपीता

स्किन का निखान बढ़ाने के लिए आप चेहरे पर पपीते का पेस्ट भी लगा सकती हैं। ब्यूटी एक्सपर्ट की मानें, तो फेस पर पपीते का पेस्ट लगाना काफी अच्छा होता है। पपीते का पेस्ट चेहरे पर अप्लाई करने से रंगत में भी सुधार होता है।

एलोवेरा जेल

स्किन के अलावा बालों के लिए भी यह काफी अच्छा माना जाता है। अगर आप सर्दियों में अपने चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाते हैं, तो आप अपना खोया निखार वापस पा सकते हैं। इसके लिए आपको सप्ताह में दो बार अपने फेस पर एलोवेरा जेल अप्लाई करना चाहिए।

कुम्भलगढ़ पर्यटन स्थल: राजस्थान का ऐतिहासिक किला और धरोहर

कुम्भलगढ़ किला, जिसे 'राजस्थान का ग्रेट वॉल' भी कहा जाता है, कुम्भलगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। यह किला 15वीं शताब्दी में राणा कुम्भा द्वारा बनवाया गया था और यह किला मेवाड़ साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण किला था।

राजस्थान का कुम्भलगढ़ किला भारतीय इतिहास और स्थापत्य कला का एक अद्वितीय उदाहरण है। यह किला राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है और यह भारतीय किलों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कुम्भलगढ़ किला अपनी विशाल दीवारों, भव्य वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के कारण प्रसिद्ध है। यह किला केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि राजस्थान की शाही धरोहर का प्रतीक भी है। कुम्भलगढ़ को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। आइए, जानते हैं कुम्भलगढ़ के प्रमुख आकर्षण और इसके महत्व के बारे में।

1. कुम्भलगढ़ किला

कुम्भलगढ़ किला, जिसे 'राजस्थान का ग्रेट वॉल' भी कहा जाता है, कुम्भलगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। यह किला 15वीं शताब्दी में राणा कुम्भा द्वारा बनवाया गया था और यह किला मेवाड़ साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण किला था। किले की दीवारें लगभग 36 किलोमीटर लंबी हैं, जो इसे दुनिया की दूसरी सबसे लंबी किलावाली दीवार बनाती हैं, केवल चीन की दीवार के बाद। कुम्भलगढ़ किले का किला परिसर बहुत विशाल है और इसमें कई महल, मंदिर और जलाशय हैं। किले की दीवारों पर चढ़कर आप कुम्भलगढ़ और आसपास के क्षेत्र का शानदार दृश्य देख सकते हैं।

2. बड़ी सीढ़ियाँ (Ramparts)

कुम्भलगढ़ किले की विशाल दीवारों के आसपास बड़ी सीढ़ियाँ हैं, जिन पर चढ़ते हुए पर्यटक किले के विभिन्न हिस्सों को देख सकते हैं। इन सीढ़ियों से किले के भीतर के अन्य महलों और संरचनाओं का दृश्य अद्भुत होता है। किले की दीवारों पर बनी मजबूत संरचना यह दर्शाती है कि किले का निर्माण युद्ध की दृष्टि से बहुत ही मजबूत और प्रभावशाली था।

3. कुम्भलगढ़ किला के महल

कुम्भलगढ़ किले में कई महल स्थित हैं, जिनमें सबसे प्रमुख महल राणा कुम्भा महल है। इस महल का वास्तुशिल्प राजपूत शैली का अद्भुत उदाहरण है। इस महल में राजपूत शाही परिवार के लिए शानदार कक्ष, जलाशय और स्विमिंग पूल भी बनाए गए थे। महल के अंदर एक संग्रहालय भी है, जहाँ कुम्भलगढ़ किले के इतिहास और यहां रहने वाले शासकों के बारे में जानकारी मिलती है।

4. कुम्भलगढ़ के मंदिर

कुम्भलगढ़ किले के भीतर कई मंदिर स्थित हैं, जो किले की ऐतिहासिकता और धार्मिक महत्व को दर्शाते हैं। इनमें से कुछ प्रसिद्ध मंदिरों में लक्ष्मी नारायण मंदिर और सिद्धनाथ मंदिर हैं। इन मंदिरों में प्राचीन मूर्तियों और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। ये मंदिर दर्शाते हैं कि कुम्भलगढ़ सिर्फ एक किला ही नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण स्थल था।

5. कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य (Kumbhalgarh Wildlife Sanctuary)

कुम्भलगढ़ किले के आसपास स्थित कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, एक शांतिपूर्ण और प्राकृतिक स्थल है। यहाँ की घने जंगलों में विभिन्न प्रकार के जीव-जंतु और पक्षी पाए जाते हैं। पर्यटक यहाँ जैव विविधता का आनंद ले सकते हैं और जंगली जीवन के करीब जा सकते हैं। अभयारण्य में ट्रैकिंग और अन्य साहसिक गतिविधियाँ भी उपलब्ध हैं।

6. कुम्भलगढ़ किले का सूर्यास्त

कुम्भलगढ़ किला सूर्यास्त के समय बेहद सुंदर नजर आता है। किले की दीवारों पर चढ़कर सूर्यास्त का दृश्य देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। यह दृश्य न केवल मनोहक है, बल्कि यह पर्यटकों को शांति और सुकून का अनुभव भी कराता है।

7. कुम्भलगढ़ में फेस्टिवल्स और इवेंट्स

कुम्भलगढ़ किले में समय-समय पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, महोत्सव और प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। यहाँ का कुम्भलगढ़ महोत्सव एक प्रमुख उत्सव है, जिसमें राजस्थान की पारंपरिक संगीत, नृत्य और शिल्पकला का प्रदर्शन किया जाता है। यह महोत्सव किले के ऐतिहासिक महत्व को फिर से जीवित करता है और पर्यटकों को एक शानदार सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करता है।

कैसे पहुंचे कुम्भलगढ़ ?

हवाई मार्ग: कुम्भलगढ़ का निकटतम एयरपोर्ट उदयपुर में स्थित है, जो कुम्भलगढ़ से लगभग 85 किलोमीटर दूर है। उदयपुर से टैक्सी या बस द्वारा कुम्भलगढ़ पहुंचा जा सकता है।

रेल मार्ग: कुम्भलगढ़ का निकटतम रेलवे स्टेशन नाथद्वारा रेलवे स्टेशन है, जो कुम्भलगढ़ से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। आप नाथद्वारा स्टेशन से कुम्भलगढ़ के लिए टैक्सी ले सकते हैं।

सड़क मार्ग: कुम्भलगढ़ सड़क मार्ग से भी अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। उदयपुर, राजसमंद और अन्य प्रमुख शहरों से कुम्भलगढ़ के लिए बसें और टैक्सियाँ उपलब्ध हैं।

सर्वोत्तम समय

कुम्भलगढ़ घूमने का सर्वोत्तम समय अक्टूबर से मार्च के बीच होता है, जब मौसम ठंडा और सुखद रहता है। गर्मियों में यहाँ का तापमान बहुत बढ़ सकता है, इसलिए इस मौसम में यात्रा करने से बचना चाहिए।

कुम्भलगढ़ किला राजस्थान का एक अद्भुत पर्यटन स्थल है, जो ऐतिहासिकता, वास्तुकला, और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहाँ का किला, मंदिर, वन्यजीव अभयारण्य और सूर्यास्त के दृश्य पर्यटकों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करते हैं। कुम्भलगढ़ ना सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि यह शांति, सुंदरता और रोमांच का भी एक बेहतरीन मिश्रण है। अगर आप राजस्थान की समृद्ध धरोहर को जानने के इच्छुक हैं, तो कुम्भलगढ़ एक बेहतरीन यात्रा स्थल है।

'ये लॉरेंस बिश्नोई कौन है, गुजरात की जेल से कैसे गैंग चला रहा है' , केंद्र सरकार पर भड़के केजरीवाल

दिल्ली में बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली की कानून व्यवस्था संभालने में विफल रही है। दिल्ली में हत्याएं बम विस्फोट और दुष्कर्म की घटनाएं आम हो गई हैं। दर्जन भर गैंग दिल्ली में सक्रिय हैं और अपने-अपने इलाके बांट रखे हैं।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली में कानून-व्यवस्था की खराब स्थिति को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शक्रवार को केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर बरसे। दिल्ली विधानसभा में बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार से दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में हमने स्कूल, अस्पताल, सड़कें और बिजली ठीक करने की जिम्मेदारी पूरी की है लेकिन केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली की कानून व्यवस्था संभाली नहीं जा रही है। दिल्ली में हत्याएं और बम ब्लास्ट हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अभी-अभी मैं देख रहा था कि एक वकील कह रहे थे कि सड़क पर हाथ में मोबाइल फोन ले जाना मुश्किल है। आप मोबाइल फोन लो जाओगे, कोई ना कोई आपका मोबाइल छीन लेगा। दिल्ली में दुष्कर्म हो रहे हैं, मर्डर कर देते हैं। मैं यह एक अखबार लेकर आया हूं। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर इसमें जानकारी दी गई है।

दिल्ली में दर्जन भर गैंग सक्रिय हैं: केजरीवाल

उन्होंने कहा कि आपके पड़ोस में गैंगवार शुरू हो गए हैं। ये लॉरेंस बिश्नोई कौन है? कैसे वह जेल में बैठ कर गैंग चला रहा है। इसके बारे में अमित शाह को बताना पड़ेगा। बिश्नोई गैंग, भाऊ ग्रैंड, गोगी गैंग... ऐसे दर्जन भर गैंग दिल्ली के अंदर सक्रिय हैं। कोई बता रहा था कि इन्होंने अपने एरिया बांट रखे हैं।

लॉरेंस बिश्नोई गुजरात में बैठकर गैंग कैसे चला रहा है: केजरीवाल

दिल्ली में कानून व्यवस्था का यह हाल हो गया है कि आज हर कोई डरा हुआ है। लोगों को वसूली के फोन आ रहे हैं। महिलाओं का रेप कर हत्या की जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने आतंक मचा रखा है। एक बात समझ नहीं आ रही कि लॉरेंस बिश्नोई BJP शासित गुजरात की साबरमती जेल में बंद है तो वह जेल में रहकर अपनी गैंग कैसे चला रहा है?

जब दिल्ली में मातायें गैंगवार में अपने बच्चों को खो रही थी। तब अमित शाह चुनावी रैलियां कर रहे थे। आज दुनिया में दिल्ली को 'गैंगस्टर कैपिटल' के नाम से जाना जाता है। अमित शाह जी जवाब दें कि क्यों दिल्ली में अपराधी इतना बेखौफ हो गए हैं? - अरविंद केजरीवाल

दिल्ली में 20 हजार परिवार में 1832 अपराध के शिकार: सिसोदिया

वहीं मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में हर 20,000 परिवार में से 1832 परिवार अपराध के शिकार हो रहे हैं। मतलब लगभग 10% दिल्ली के परिवार अपराध के शिकार हो रहे हैं और यह लोग जी-20 में कुछ नहीं हुआ, जी-20 में कुछ नहीं हुआ है, कर रहे हैं। लोग डर रहे हैं। धमकियां गोली बारी हो रही है।

सदन में स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का मुद्दा उठा

बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता द्वारा विधानसभा सदन में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट का मुद्दा उठाने पर सदन में हंगामा हो गया। सत्ता पक्ष के विधायकों के बाद विपक्ष के विधायकों ने भी हंगामा किया। विधानसभा अध्यक्ष ने विजेंद्र गुप्ता और विपक्ष के अन्य सदस्यों को मार्शल आउट किया। उनके द्वारा बोली गई सभी बातों को सदन से कार्रवाई से निकाला गया। बाद में सदन की कार्यवाही को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

विधानसभा में कैग रिपोर्ट हो पेश' , उपराज्यपाल ने फिर लिखा सीएम आतिशी को पत्र

दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया और कार्यवाही के दौरान हंगामे के बाद बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं इसी बीच एलजी वीके सक्सेना ने सीएम आतिशी को पत्र लिखकर एक बार फिर से कैग रिपोर्ट सदन पटल पर पेश करने को कहा है। इनमें से कुछ कैग रिपोर्ट 2022 से लंबित हैं।

नई दिल्ली। विधानसभा सत्र की शुरुआत के साथ ही एलजी वीके सक्सेना ने सीएम आतिशी को पत्र लिखकर एक बार फिर कैग की रिपोर्ट सदन पटल पर रखने को कहा है। यह रिपोर्टें वर्षों से लंबित है। इससे पूर्व भी एलजी ने तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल (Ram Niwas Goel) को इसके लिए पत्र लिखा था।

एलजी (VK Saxena) ने पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि इन रिपोर्टों को चालू सत्र में पेश किया जाए। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आतिशी (CM Atishi) को लिखे पत्र में एलजी ने जिक्र किया है कि कैग की रिपोर्ट लगातार पेश करने के लिए लिखता रहा, लेकिन एक सरकार जो पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दे पर सत्ता में आई थी।

सरकार पर अलग-अलग विभागों की 12 रिपोर्ट दबाने का आरोप

जानबूझकर खर्च की सार्वजनिक जांच से बच रही है। इससे पूर्व 17 अगस्त को एलजी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कैग की रिपोर्ट सदन पटल पर रखने को कहा था। एलजी ने आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली सरकार पर अलग-अलग विभागों की कुल 12 कैग रिपोर्ट दबाने का आरोप लगाया है।

एलजी (दिल्ली के उपराज्यपाल) ने सरकार के वित्त, प्रदूषण, दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति, सार्वजनिक उपक्रमों और सामाजिक और सामान्य क्षेत्रों से संबंधित विभागों के खातों और शेल्टर होम से संबंधित कैग रिपोर्ट मुख्यमंत्री आतिशी के पास लंबित होने की बात कही है। इनमें से कुछ कैग रिपोर्ट 2022 से लंबित हैं।

सीएम आतिशी के पास ऑडिट रिपोर्ट है लंबित-एलजी का पत्र

एलजी ने पत्र में लिखा है कि ₹वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान दिल्ली में शराब की खरीद-बिक्री से संबंधित ऑडिट पर कैग की रिपोर्ट चार मार्च 2024 को दिल्ली सरकार को भेजी गई थी, यह 11 अप्रैल 2024 से आतिशी (जब वे वित्तमंत्री थीं) के पास लंबित है।

दिल्ली सरकार की विवादास्पद दिल्ली आबकारी नीति और उसकी ऑडिट रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। एलजी सचिवालय की तरफ से लिखा गया है कि 18 जुलाई 2024 को दिल्ली के लेखा नियंत्रक ने एलजी सचिवालय को सूचित किया था कि उपरोक्त सभी कैग ऑडिट रिपोर्ट आतिशी के पास लंबित हैं।

ऑनलाइन-ऑफलाइन सदस्यता अभियान चलाकर देशभर में 2 करोड़ नए सदस्यों को आरपीआई से जोड़ने का लक्ष्य: रामदास आठवले

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आ.) ने राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक की अध्यक्षता करते हुए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया(आठवले) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. रामदास आठवले ने कहा कि सभी प्रदेशों के अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी पार्टी के वृहद सदस्यता अभियान में सक्रियता से भाग लेकर 2 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य हासिल करे।

नई दिल्ली। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले ने कहा कि पार्टी ने आज सदस्यों को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए डिजिटल सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया है। आठवले ने कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के लिए सभी पदाधिकारियों को आम जनता से संपर्क कर अधिक से अधिक संख्या में लोगों को डिजिटल रूप से पार्टी से जोड़ने के लिए संकल्पित होना चाहिए। बैठक में आरपीआई को गांव गांव तक मजबूत कर आम जनमानस को केंद्र की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने को लेकर भी विशेष चर्चा की गई।

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आ.) ने राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक की अध्यक्षता करते हुए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया(आठवले) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. रामदास आठवले ने कहा कि सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी पार्टी के वृहद सदस्यता अभियान में सक्रियता से भाग लेकर 2 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य हासिल करे।

आरपीआई (आठवले) के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आ) बाबासाहेब के आदर्शों व विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है । रामदास आठवले ने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता वृहत सदस्यता अभियान में सक्रियता से अपनी भागीदारी दे तथा ग्राम, ब्लॉक स्तर पर भी कमेटियां गठित कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। मा. रामदास आठवले ने कहा कि सदस्यता अभियान चलाकर देशभर में 2 करोड़ नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ने का हमारा लक्ष्य है।

रामदास आठवले ने कहा कि सभी पदाधिकारियों को अपने राज्य, जिला व ब्लॉक में आम जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आंदोलन चलाकर उन समस्याओं के निराकरण का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए, जिससे जनजन में पार्टी की पहुंच बढ़ेगी तथा पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिलने में ये सहायक सिद्ध होगा। आठवले ने कहा कि आने वाले दिनों में बाबासाहेब के विचारों को आगे बढ़ाते हुए एससी, एसटी, ओबीसी सहित समाज के वंचित, शोषित, महिलाओं व अन्य वर्ग के लोगों के कल्याण व उत्थान के लिए आरपीआई कार्यकर्ताओं को हरसंभव प्रयास करना चाहिए।

किसानों की फिर से दिल्ली कूच की तैयारी, यीडा के दफ्तर के बाहर दूसरे दिन भी धरना जारी

यमुना प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का गुस्सा दूसरे दिन भी लगातार जारी रहा। किसानों और महिलाओं ने प्राधिकरण कार्यालय के बाहर धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। किसान 10 प्रतिशत आबादी भूखंड और नए भूमि अधिग्रहण कानून के सभी लाभ की मांग कर रहे हैं। किसानों ने यीडा कार्यालय की पार्किंग में टेंट लगाकर महापड़ाव शुरू किया। जो रविवार तक चलेगा।

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर तीन दिन महापड़ाव के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान संगठनों ने बृहस्पतिवार को यमुना प्राधिकरण के खिलाफ हुंकार भरी। उनकी यह हुंकार दूसरे दिन भी जारी रही।

ग्रेटर नोएडा से पैदल, ट्रैक्टर ट्रॉली, बाइक और चार पहिया वाहनों में सवार होकर प्राधिकरण के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हजारों किसान यमुना प्राधिकरण (यीडा) के कार्यालय पहुंचे। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए प्राधिकरण कार्यालय पर सुबह से ही पुलिस बल ने मोर्चा संभाल रखा था।

गेट पर लगे बैरिकेड को तोड़ते हुए किसानों ने जैसे ही प्राधिकरण कार्यालय में प्रवेश करने का प्रयास किया, पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस व किसानों के बीच नोकझोंक भी हुई।

दो दिसंबर को किसान करेंगे दिल्ली कूच

इसके बाद किसान पार्किंग स्थल में धरना देकर बैठ गए। किसानों ने यीडा कार्यालय की पार्किंग में टेंट लगाकर महापड़ाव शुरू कर दिया है। यह रविवार तक चलेगा। दो दिसंबर को किसान दिल्ली कूच करेंगे। बृहस्पतिवार करीब तीन बजे किसानों ने यमुना प्राधिकरण कार्यालय की ओर कूच किया।

सड़कों पर किसानों के पैदल मार्च और वाहनों के कारण परीचौक पर भी जाम की स्थिति बन गई। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे होते हुए किसान यीडा कार्यालय पहुंचे जहां पुलिस ने पहले से ही सड़क पर बैरिकेड लगा रखे थे। ट्रैक्टर ट्राली से बैरिकेड को तोड़ते हुए किसान प्राधिकरण कार्यालय के परिसर में दाखिल हो गए।

किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पहले ही लोहे के चैनल को बंद कर दिया गया था। सर्विस रोड व मुख्य सड़क की एक साइड पर भी वाहनों के कारण आवाजाही ठप हो गई। आगे चल रही महिलाओं ने कार्यालय में प्रवेश की कोशिश की, लेकिन पुलिस व सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया।

किसानों की है प्रमुख मांगे

इसके बाद किसानों ने धरना शुरू कर दिया। भारतीय किसान यूनियन के पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पवन खटाना ने कहा कि 10 प्रतिशत आबादी भूखंड और नए भूमि अधिग्रहण कानून के सभी लाभ की मांग लंबे समय से की जा रही है। प्राधिकरण और शासन की हठधर्मिता से किसानों को इनसे वंचित रखा जा रहा है।

जय जवान जय किसान मोर्चा के सुनील फौजी ने कहा किसानों को 10 प्रतिशत भूखंड और 64.7 प्रतिशत बढ़ा मुआवजा, नए भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ के साथ बाजार दर का चार गुना मुआवजा, भूमिधर और भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार तथा पुनर्वास के लाभ मिलने चाहिए। विकास प्रधान ने कहा कि किसान अब अपना शोषण बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है।

किसानों के महापड़ाव में जय जवान जय किसान मोर्चा, अखिल भारतीय भारतीय किसान सभा, भारतीय किसान परिषद, किसान एकता संघ, किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा तथा भाकियू कृषक शक्ति, भाकियू अजगर और सिस्टम सुधार आदि संगठनों के कार्यकर्ता थे।

शारीरिक संतुष्टि के लिए मौत को गले लगाते युवा

सुभाष आनंद -विनायक फीचर्स

यह आम कहावत है कि लोग बुरी आदतों को शीघ्र सीख लेते हैं जबकि अच्छी आदत सीखने में उन्हें देर लगती है। एक नए अध्ययन में बताया गया है कि आजकल लोग अजीबो गरीब हरकतें करके खुशी मनाने के चक्कर में मौत के मुंह में चले जाते हैं। इनमें नदी, समुद्र या बांध के किनारे सेल्फी लेने, सड़कों पर मोटरसाइकिल पर कलाबाजियां करते समय जीवन से हाथ धो बैठते हैं। एक अध्ययन में कुछ नये खुलासे भी हुए हैं। ताजातरीन अध्ययन यह है कि आजकल पंजाब में नौजवान हस्तमैथुन करते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त कर बैठते हैं। यद्यपि पंजाब सरकार के पास इसके सही आंकड़े मौजूद नहीं है परंतु शहरों में सेक्स विशेषज्ञों से बातचीत करने के पश्चात कई कटु सच्चाइयां सामने आई है। लुधियाना में एक 19 वर्षीय बच्चा हस्तमैथुन का इतना आदि हो गया कि उसके शरीर की शक्ति क्षीण हो गयी और उसकी मृत्यु हो गई।

ऐसा ही एक व्यक्ति और मृत पाया मिला जिसने बिजली के करंट के माध्यम से अपने शरीर में कामोत्तेजना पैदा करने के लिए लाइटों को अपने शरीर से जोड़ा हुआ था।

सेक्स विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश गोयल का कहना है कि पंजाब में लोग नई-नई जुगाड़ लगाते रहते हैं। नशेड़ी लोग भी सेक्स का चरम सुख प्राप्त करने के लिए ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करते रहते हैं। कामोत्तेजना की अभिलाषा से हुई इन मौतों का कारण बताते हुए फॉरेंसिक परीक्षक सुखदेव सिंह का कहना है कि ऐसे लोग शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम करके चरम कामोत्तेजना का आनंद उठाते हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब में हर वर्ष जोखिम भरी हस्तमैथुन प्रक्रियाओं के कारण 90 से 100 नौजवान मौत का शिकार हो रहे हैं।

अध्ययन से यह भी खुलासा हुआ है कि पंजाब की 10 लाख आबादी पर प्रतिवर्ष एक या दो मौतें ऐसी होती है जिनमें यौन क्रिया को अधिक उत्तेजना पूर्वक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण या जुगाड़ प्रयोग में लाए जाते हैं।

वहीं अमृतसर के रहने वाले एक मृत व्यक्ति के कमरे से पोनोग्राफी सामग्री भी मौजूद मिली थी। यहां जांचकर्ताओं का अनुमान है कि वह कामोत्तेजना का सुख हासिल करने के प्रयास में मौत के मुंह में चला गया। एक आदमी की माछीवाड़ा कस्बे में घर के तहखाने में मौत हो गई ,उसने अपने आप को जंजीरों में बांध रखा था।

फिरोजपुर के एक नामी पत्रकार का कहना है कि कई मामले समाचार पत्रों में नहीं आते ,लेकिन उनकी संख्या वास्तविकता में कहीं अधिक होती है। ऐसी मौतों के शिकार लोगों के रिश्तेदार प्राय : सामाजिक शर्मिंदगी से बचने के लिए ऐसे मामलों की पुलिस में रिपोर्ट नहीं करते।

वही जालंधर के रहने वाले 16 वर्षीय युवा को हस्तमैथुन की इतनी भयंकर आदत थी कि उसके माता-पिता रात्रि को सोते समय उसकी दोनों भुजाओं को पलंग से बांध देते थे।

डॉक्टर ऋचा शर्मा का कहना है कि ऐसे रोगियों को प्राय : रात्रि के समय नशे की डोज दी जाती है ताकि वह नींद में ऐसी हरकतें ना कर सके। ग्रामीण क्षेत्रों में जिन युवाओं के विवाह में देरी हो रही है उनमें यह रोग बड़ी तेजी से फैल रहा है लेकिन मरीज ऐसी बीमारियों का इलाज करने से शर्माते हैं और डॉक्टरों को दिखाने से परहेज करते हैं।

समाज में बढ़ती इस बुराई को दूर करने के लिए समाजसेवी संस्थाओं को भी समाज को जागृत करना चाहिए। पंजाब सरकार के स्वास्थ्य विभाग को भी नौजवानों को इस समस्या से दूर रहने के लिए शीघ्र अभियान छेड़ने की जरूरत है।

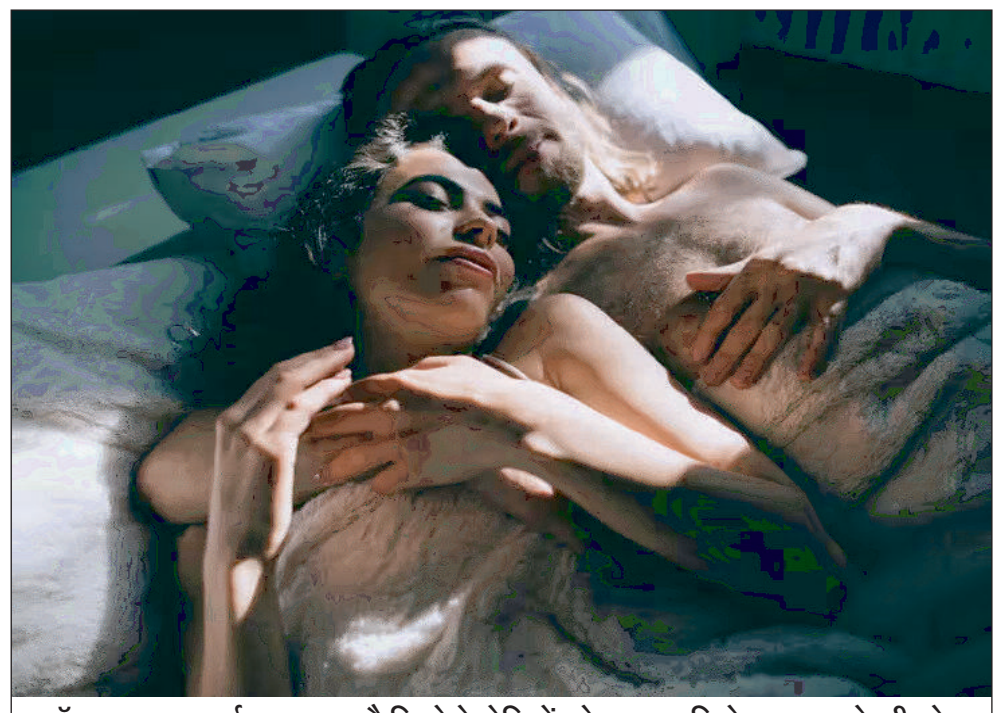

डॉक्टर ऋचा शर्मा का कहना है कि ऐसे रोगियों को प्राय : रात्रि के समय नशे की डोज दी जाती है ताकि वह नींद में ऐसी हरकतें ना कर सके। ग्रामीण क्षेत्रों में जिन युवाओं के विवाह में देरी हो रही है उनमें यह रोग बड़ी तेजी से फैल रहा है लेकिन मरीज ऐसी बीमारियों का इलाज करने से शर्माते हैं और डॉक्टरों को दिखाने से परहेज करते हैं।

पिछले दिनों प्रभातशाह वाला गांव में एक नौजवान को जंजीरों से बंधा पाया गया, जब पंजाब पुलिस की टीम वहां गई तो उनके मां-बाप ने दुख भरी दास्तां बताते हुए कहा कि यह दिन रात हस्तमैथुन का आदी है। अतः हमने दुखी होकर इसे जंजीरों में बंद किया है। वही दिल्ली ऑल इंडिया मेडिकल के सेक्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्जुन त्रिवेदी का कहना है कि पंजाब और हरियाणा में विवाह में देरी हो रही है, जिसके कारण नौजवान सेक्स संतुष्टि के लिए हस्तमैथुन का आसान रास्ता अपना रहे है।

उन्होंने आगे यह कहा कि समाज में पोर्न पिक्चरों की बुराई भी नौजवानों को मुश्किल में डाल रही है। महिलाओं में भी पोर्न पिक्चरों का क्रेज बढ़ता जा रहा है। हरियाणा, पंजाब में भी पोर्न पिक्चरों पर सरकार की कोई पाबंदी नहीं है, इस सोशल बुराई को समाप्त करने के लिए सभी सरकारों को आगे आना चाहिए।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज पंजाब की गली-गली ,मोहल्ले मोहल्ले और गांवों में पोर्न पिक्चरों का बोलबाला है। सोशल मीडिया पर पोर्न पिक्चर को लेकर घर घर में क्लेश बना हुआ है। पोर्न के आदी पतियों से तंग परेशान पत्नियों ने कोर्ट का सहारा लिया हुआ है।अमृतसर की एक विवाहित युवा महिला ने कहा कि उसका पति नेट के जरिए पोर्न फिल्में देखने का आदी है ,वह पोर्न का विक्टिम हो चुका है। इस महिला ने कोर्ट से तुरंत इंसाफ दिलवाने की अपील की है।

प्रशासन की इस पहल से साइबर सिटी होगी साफ-सुथरी, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कर रहे निजी वाहन भी होंगे जब्त

गुरुग्राम की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मंडलायुक्त आरसी बिढ़ान ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अवैध रूप से दिल्ली से आने वाले कूड़े दुकानों के बाहर कूड़े के सही तरीके से निस्तारण न किए जाने और गांव चकरपुर के प्रवेश द्वार पर प्राइवेट संस्थानों द्वारा कूड़ा डाले जाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। मंडलायुक्त ने इन समस्याओं के समाधान के लिए सख्त निर्देश दिए।

गुरुग्राम। गुरुग्राम जिले की सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मंडलायुक्त आरसी बिढ़ान ने विधायक मुकेश शर्मा की मौजूदगी में अधिकारियों के साथ शुक्रवार को बैठक की। इसमें स्वच्छता अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की गई। बैठक में निर्देश दिया गया कि शहर में जहां कहीं भी प्राइवेट लोग डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कर पैसे वसूल रहे हैं।

ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उनके वाहनों को जब्त किया जाए। सफाई अभियान की मॉनिटरिंग के लिए नियुक्त सभी संबंधित अधिकारी अपने वार्ड में सुबह व शाम सफाई कर्मचारियों का हाजिरी रजिस्टर जरूर चेक करें ताकि लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।

पिछले कुछ महीनों से साइबर सिटी की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। बैठक पर बैठक आयोजित की जा रही है लेकिन स्थिति नियंत्रण में नहीं। इसे देखते हुए मंडलायुक्त आरसी बिढ़ान ने अधिकारियों के साथ लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हाल में बैठक की।

बैठक में विशेष रूप से मौजूद विधायक मुकेश शर्मा ने कहा कि अवैध रूप से दिल्ली से आने वाला कूड़ा शहर की सफाई व्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। मध्यरात्रि के समय गुरुग्राम के बजघेड़ा, सेक्टर 21, वजीराबाद व कार्टरपुरी में निरंतर से दिल्ली से आने वाले गाड़ियों द्वारा कूड़ा डंप किया जा रहा है।

इस पर मंडलायुक्त ने नगर निगम के संयुक्त आयुक्त, जिला प्रशासन व पुलिस विभाग व आरटीए विभाग से एक-एक अधिकारी की चार सदस्यीय टीम गठित कर रात्रि के समय विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने विधायक की शिकायत पर शहर में दुकानों के बाहर कूड़े का सही तरीके से निस्तारण नहीं किए जाने के संबंध में निगम अधिकारियों को ऐसे दुकानदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के

निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निगम अधिकारी सभी दुकानदारों को आगाह करते हुए यह सुनिश्चित करें कि वे दुकानों के बाहर डस्टबीन जरूर रखें।

इसके बाद भी यदि कोई दुकानदार नियमों की अवहेलना करता है तो उसका चालान किया जाए। विधायक ने यह भी कहा कि गांव चकरपुर के प्रवेश द्वार पर प्राइवेट संस्थानों द्वारा कूड़ा डाला जा रहा है। जिससे उस रास्ते पर लोगों की आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। मंडलायुक्त ने इस विषय पर संज्ञान लेते हुए स्थान की सफाई के साथ ही अगले एक हफ्ते तक वहां मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए।

मंडलायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि शहर में जितने भी जीवी प्वाइंट्स व सेकंडरी प्वाइंट्स हैं, वहां 24 घंटे ट्रॉली व डंपर अवश्य खड़े हों। उन्होंने सैनेटरी इंस्पेक्टरों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए उन्हें रविवार तक सभी चिन्हित स्थानों की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा। उन्होंने कहा कि सफाई की स्पष्ट परिभाषा यही है कि संबंधित क्षेत्र में 24 घंटे सातों दिन कूड़े का एक भी अंश दिखाई न दे।

अभियान में नियुक्त अधिकारी उक्त परिभाषा के लक्ष्यों के साथ प्लानिंग करेंगे तो आमजन के सहयोग से हम जल्द ही अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। आमजन को बेहतर सफाई व्यवस्था व स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के अभियान में किसी भी स्तर पर लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। बैठक में उपायुक्त अजय कुमार, नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त अशोक कुमार गर्ग सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

फैमिली आईडी से मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ, बनवाने के लिए करें आवेदन; पढ़ें पूरी डिटेल्स

नोएडा। सरकार की तरफ से संचालित की जा रही लाभार्थीपरक योजनाओं का लाभ अब आमजन को विशिष्ट फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान के तहत दी जानी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में तकनीकी समस्या आने से बीच में प्रक्रिया की धीमी शुरुआत हुई।

हजारों की संख्या में निरस्त किए जा चुके आवेदन

वहीं, सत्यापन के स्तर पर गड़बड़ी होने से हजारों की संख्या में आवेदन निरस्त किए जा चुके हैं। इधर बीते दो सप्ताह से एक बार फिर डीएम ने फैमिली आईडी बनवाए जाने की प्रक्रिया में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए हैं।

सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में मदद करेगी यह फैमिली आईडी

प्रदेश में सभी परिवारों की एक विशिष्ट पहचान हो इसके लिए फैमिली आईडी बनवाना अनिवार्य किया गया है। इस योजना में ऐसे परिवार जिनके पास राशनकार्ड नहीं है और मानकों के तहत उनको राशन कार्ड की सुविधा नहीं दी जा सकती। उन्हें यह फैमिली आईडी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में लाभप्रद साबित होगी।

अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं

बताया गया कि जिन परिवारों के पास विभिन्न राशन योजनाओं के तहत राशनकार्ड हैं यह कार्ड ही उनकी फैमिली आईडी हैं उनको अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है।

लेखपाल देंगे संबंधित परिवार की रिपोर्ट

डीएसओ ओमहरि उपाध्याय ने बताया कि जिले में शहरी क्षेत्र में एसडीएम जहां सत्यापन अधिकारी हैं तो लेखपाल संबंधित परिवार की रिपोर्ट देंगे।

ऐसे बनाई जा सकेगी फैमिली आईडी

वहीं, ग्रामीण क्षेत्र में सत्यापन अधिकारी खंड विकास अधिकारी को बनाया गया है, यहां पर पंचायत सचिव आवेदन पर अपनी रिपोर्ट देंगे उसके बाद फैमिली आईडी बनाई जा सकेगी। ऑनलाइन इसको डाउनलोड कर प्रयोग में लाया जा सकता है।

8186 परिवारों ने किया आवेदन, 1018 को मिली स्वीकृति

डीएसओ ओमहरि उपाध्याय ने बताया कि अब तक जिले में कुल 8186 परिवारों ने फैमिली आईडी के लिए आनलाइन आवेदन किया है। इसमें सत्यापन के बाद 1018 परिवारों को फैमिली आईडी बनाए जाने की स्वीकृति दी जा चुकी है। वहीं तकनीकी व व्यवहारिक कमियों के कारण 6345 आवेदन निरस्त किए गए हैं।

ई-ऑफिस में बदले जाएंगे यीडा के पांच विभाग, अब फटाफट होंगे लोगों के रुके काम

=यमुना प्राधिकरण जमीनी विवादों के समाधान और आवंटियों से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के लिए पांच विभागों को ई-ऑफिस में बदलने जा रहा है। इस कदम से आवंटियों को अपने काम कराने के लिए अब विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और फाइलों के गुम होने की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। लेख में पढ़ें पूरी खबर।

नोएडा। जमीनी विवाद के हल और आवंटियों से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के लिए यमुना प्राधिकरण (यीडा) पांच विभागों को ई आफिस बनाने जा रहा है। इन विभागों से जुड़े सभी कार्य सोमवार से आनलाइन ही किए जाएंगे। विभागों की पुरानी फाइलों को भी डिजिटल बनाकर अपलोड किया जाएगा।

यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) काफी वक्त से अपने कार्यालय को ई-ऑफिस में तब्दील करने के प्रयास कर रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी है। बड़ी संख्या में फाइलों का डिजिटल प्रारूप तैयार न हो पाने और कर्मचारियों को कामकाज में अड़चन से प्राधिकरण ई-ऑफिस के लक्ष्य से दूर है।

पहले चरण में पांच विभाग ई-ऑफिस में होंगे तब्दील

इसलिए प्राधिकरण ने चरणबद्ध तरीके से ई-ऑफिस का लक्ष्य पूरा करने का फैसला किया है। पहले चरण में पांच विभाग सोमवार से ई-ऑफिस में तब्दील हो जाएंगे। इन विभागों को सोमवार से सभी कार्य ऑनलाइन होगा। कर्मचारियों को फाइल लेकर अधिकारियों के कार्यालय तक भागदौड़ नहीं करनी होगी।

सभी कर्मचारियों व अधिकारियों के यूजर आईडी और पासवर्ड तैयार किए गए हैं। इसके जरिये वह फाइल में अपने कार्य को पूरा करेंगे। अधिकारी हस्ताक्षर व फाइल में हुई प्रगति की स्थिति को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकेंगे। प्राधिकरण ने ई-ऑफिस के लिए कर्मचारियों को दो दिवसीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। इसके लिए एनआईटी कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

ई-ऑफिस बनने से कर्मचारियों की बढ़ेगी दक्षता

इस संबंध में प्राधिकरण के ओएसडी एवं महाप्रबंधक परियोजना राजेश कुमार ने बताया कि सोमवार से लीगल, सिस्टम, कॉमर्शियल, एचआर और फाइनेंस विभाग पूरी तरह से ई-ऑफिस में कामकाज करेंगे। प्राधिकरण के अन्य विभागों को भी चरणबद्ध तरीके से ई-ऑफिस में बदला जाएगा। इन विभागों के ई-ऑफिस बनने से कर्मचारियों की दक्षता बढ़ेगी।

फाइलों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय लेकर होने वाली भागदौड़ व समय की बचत होगी। फाइलों के गुम होने की समस्या समाप्त होगी। अधिकारी किसी भी वक्त अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर फाइल को देख सकेंगे। आवंटियों के प्राधिकरण से संबंधित कामकाज की गति बढ़ेगी। उन्हें अपने काम कराने के लिए फाइल की स्थिति जानने को एक से दूसरे विभाग नहीं भटकना पड़ेगा।

कचहरी में हड़ताल रही जारी, मानव श्रृंखला बनाकर अधिवक्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन

गाजियाबाद में वकीलों की हड़ताल से कोर्ट में कामकाज जस का तस पड़ा है। आज के दिन को हाथ पर काली पट्टी बांधकर काले दिवस के रूप में मनाया गया। वकीलों ने शुक्रवार को मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें एक महीने से चल रही हड़ताल के कारण मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पा रही है।

नोएडा। गाजियाबाद जिला कोर्ट रूम में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज होने के विरोध में एक माह बाद शुक्रवार को भी कचहरी में हड़ताल जारी रही।

अधिवक्ताओं ने आज के दिन को हाथ पर काली पट्टी बांधकर काले दिवस के रूप में मनाया और कचहरी से कलक्ट्रेट परिसर तक मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया।

शुक्रवार को वकीलों ने बार सभागार में की बैठक

शुक्रवार को सुबह 11 बजे अधिवक्ताओं ने बार सभागार में एकत्र होकर बैठक की। उन्होंने 29 अक्टूबर को जिला जज से हुए विवाद के बाद अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज पर विरोध प्रकट किया।

इसके बाद सभी अधिवक्ता कचहरी परिसर से मानव श्रृंखला बनाकर बाहर निकले और कलक्ट्रेट की ओर जाने वाली सर्विस लेन से होकर कलक्ट्रेट परिसर के अंदर से जिला जज और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वापस कचहरी वापस लौटे।

न्यायालय परिसर के अंदर दाखिल नहीं हुए अधिवक्ता

इस दौरान अधिवक्ताओं का एक गुट न्यायालय के गेट की ओर बढ़ा, वहां गेट पर ताला लगा देखकर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ताओं के समझाने पर वे वहां से वापस लौट आए, न्यायालय परिसर के अंदर अधिवक्ता दाखिल नहीं हुए।

गाजियाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने बताया कि अधिवक्ताओं ने जिला जल के निलंबन, अधिवक्ताओं पर दर्ज एफआईआर वापस लेने, अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाने, लाठी चार्ज में जख्मी अधिवक्ताओं को मुआवजा देने और लाठीचार्ज करने वाले दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग रखी है।

वकीलों की ये हैं मुख्य मांगे

- जब तक जिला जज का निलंबन।
- लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई।
- अधिवक्ताओं के लिए प्रोटेक्शन एक्ट नहीं बनता है।

जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल रहेगी-वकील

जब तक यह पांचों मांगे पूरी नहीं होंगी। कचहरी में हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि 51 अधिवक्ताओं की एक संघर्ष समिति बनाई गई है, जो प्रतिदिन आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने का कार्य करेगी।

उधर, अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण केसों में सुनवाई न होने से वादकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अदालत में लंबित मामलों का निस्तारण नहीं हो रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2023 से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व जिम्मेदार नागरिक नीति पर ज़ोर

विज़न 2047 के आधार स्तंभों में शिक्षा की गुणवत्ता व जिम्मेदार नागरिक का महत्वपूर्ण रोल

संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि का विकसित भारत का सपना स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व जिम्मेदार नागरिक बनने पर निर्भर है,सटीक विश्लेषण- एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनांनी गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर हर देश का विकास तभी संभव होगा जब उस देश में शिक्षित नागरिकों का अधिक प्रतिशत हो,उनका हृदय दिलों दिमाग से जिम्मेदार नागरिक होने का ज़ज्बा व जांबांजी हो तो उस देश के विकास को कोई नहीं रोक सकता। मेरा मानना है कि यह उस देश की शिक्षा नीति व पाठ्यक्रम ढांचा नीति पर निर्भर करता है।अमेरिका में निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने हर चुनावी सभाओं में संघीय शिक्षा विभाग की निंदा करते नज़र आए,अब अनुमान है कि संघीय शिक्षा मंत्रालय को बंद कर राज्यों को इसका पूर्ण अधिकार दिया जा सकता है, इसलिए ही उन्होंने शिक्षा विकास की जिम्मेदारी पेशेवर रेसलर इंटीरियर की सीईओ को सौंपी है,यांने अब अमेरिकी एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो सकती है, इधर भारत में भी संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि ने बयान दिया है कि,भारत के विकास का विज़न 2047 तभी पूरा हो सकता है,जब स्कूलों में बच्चों को न केवलगुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले बल्कि उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने की भी प्रेरणा मिले।हम देखते हैं कि आज शिक्षा का स्तर 50 वर्ष पूर्व से अपेक्षाकृत कम हुआ है जिसका उदाहरण है कि पुराने जमाने के लोग किसी भी कैलकुलेशन का जवाब झट से दे देते हैं जबकि अभी के युवाओं को कैलकुलेट की जरूरत पड़ती है। आज स्कूलों में भी किसी विषय को सिर्फ पढ़कर समझाया जाता है प्रैक्टिकल रूप से नहीं समझाया जाता, मैं अपने स्कूल का 1977 का वाक्या बताना चाहूंगा जब मैं छठवीं कक्षा में था हमारे हिंदी के टीचर श्री भूरेलाल के पटले ने मुझे बुलाया और एक मज़बूत धागा देकर तोड़ने के लिए कहा मैंने तोड़ दिया फिर उन्होंने उसे जोड़ने के लिए कहा मैंने गांठ बांध दी, बस ! उन्होंने इसपर समझाया, रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय, टूटै से फिर ना मिलै,मिलै गांठ पड़ जाए, और हमें बताया रिश्तो नातों दोस्तों संबंधों को प्यार मोहब्बत से सहेज कर रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा भी रिश्ता बिगड़ा तो वह पहले जैसा नहीं रहेगा जैसे इस धागे में गांठ पड़ी दिखाई दे रही है।हमारे पूरे क्लास को आज भी रिश्ते सहेज कर रखने की यह सीख याद है यह विषय आज हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं,क्योंकि 27 नवंबर 2024 को भारत में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि ने विकसित राष्ट्र का सपना पूरा करने स्कूलों से शिक्षा की गुणवत्ता व जिम्मेदारनागरिक बनने की बात कही,इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2023 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वजिम्मेदार नागरिक नीति पर जोर देना जरूरी है।

साथियों बात कर हम नई दिल्ली में आयोजित राइजअप 4पीसी नीति बैठक की करें तो एनसीईआरटी और यूएनओडीसी साउथ एशिया की तरफ से आयोजित राइजअप4पीस नीति सलाहकार बैठक में 70 से अधिक नीति-निर्माताओं, शिक्षकों और युवा नेताओं ने भाग लिया। इस दौरान नीति निर्माताओं, शिक्षकों और छात्रों ने पाठ्यक्रम में सुधार, अच्छे अभ्यास और नए विचारों पर चर्चा की।एनसीईआरटी के संयुक्त निदेशक ने शिक्षकों से आग्रह किया कि वे क्षमताओं का निर्माण करें और मूल्य आधारित शैक्षिक मॉड्यूल विकसित करें। उन्होंने कहा,एनईपी 2020 और एनसीएफ 2023 शिक्षा को एक अधिक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज के लिए सेतु के रूप में देखते हैं। ऐसे सहयोग दृष्टि को क्रियान्वयन में बदलते हैं। इस चर्चा में यह स्पष्ट हुआ कि शिक्षा को बदलने के लिए पूरे समाज का सहयोग जरूरी है,जहां नीति निर्माता शिक्षक और छात्र समान भागीदार हों। इस दिशा में प्रयास संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करें। इस पहल ने इस वर्ष 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 हज़ार से अधिक भागीदारों को शामिल किया है।इसमें शिक्षकों का प्रशिक्षण, स्कूल आधारित पहल और छात्रों के लिए गतिविधि-आधारित शिक्षण शामिल है।कला, प्रौद्योगिकी और खेल का उपयोग करके छात्रों को सशक्त बनाने के लिए अभिनव हस्तक्षेप किए गए। यह पहल युवाओं को नकारात्मक प्रभावों, नई कमजोरियों और जोखिमपूर्ण व्यवहारों का विरोध करने के लिए जागरूक और सशक्त बनाने पर केंद्रित है। उन्होंने बताया कि पीएम की तरफ से कल्पित विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा मिले।परिवर्तन के वाहक के रूप में भारत के विद्यार्थियों की विपुल क्षमता का उल्लेख करते हुए देश में संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय समन्वयक ने कहा है कि विकसित भारत का सपना यह सुनिश्चित करने पर टिका है कि विद्यालय में बच्चों को न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, बल्कि उन्हें कल के जिम्मेदार आदर्श नागरिक बनने के लिए भी संवेदनशील बनाया जाए।

साथियों बात अगर हम भारत में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि के विचारों की करें तो उन्होंने एक बयान में कहा, कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा हो सकता है, जब स्कूलों में बच्चों को न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, बल्कि उन्हें

जिम्मेदार और आदर्श नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया जाए।भारत के 26.52 करोड़ छात्रों में बदलाव के प्रेरक बनने की जबरदस्त क्षमता है।उन्होंने समावेशी और शांतिपूर्ण समाज बनाने में गुणवत्तापूर्ण और मूल्यों पर आधारित शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया। यह पहल युवाओं को नकारात्मक प्रभावों, नई कमजोरियों और जोखिमपूर्ण व्यवहारों का विरोध करने के लिए जागरूक और सशक्त बनाने पर केंद्रित है।उन्होंने बताया कि पीएम की तरफ से कल्पित विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा मिले। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी) और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2023 (एनसीएफ) इस बात को स्वीकार करते हैं कि जिम्मेदार नागरिकों को तैयार करना, जो शांति और सद्भाव में योगदान दे सकें,अत्यंतआवश्यक है। इस महत्वाकांक्षा के वास्ते शिक्षा के पारंपरिक दायरे से आगे जाना होगा-इसके लिए कक्षाओं, स्कूलों और समुदायों में शैक्षिक हस्तक्षेप की पुनःकल्पना की जरूरत है।बयान में कहा गया है कि भारत में चहलपहल वाली कई कक्षाओं में,एक शक्तिशाली आंदोलन चुपचाप आकार ले रहा है,एक ऐसा आंदोलन जो शिक्षा के माध्यम से शांति, कानून के प्रति निष्ठा और समावेशन को बढ़ावा देता है।बयान में कहा गया है कि इस आंदोलन के केंद्र में सिर्फ़ नीति निर्माता, शिक्षक या संस्थान ही नहीं हैं, बल्कि युवा लोग हैं जो बदलाव के सबसे महत्वपूर्ण वाहक के रूप में खड़े हैं।भारत के शीर्ष पाठ्यक्रम निकाय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) और यूएनओडीसी दक्षिण एशिया द्वारा यहां आयोजित राइजअप4पीस नीति नामक परिचर्चा में पहल की प्रासंगिकता और प्रभाव पर जोर देते हुए, 70 से अधिक नीति-निर्माताओं, शिक्षकों और युवा चैंपियनों ने शिक्षा में शांति, समावेशन और कानून के प्रति को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप तैयार किया जैसा कि एनईपी 2020 और एनसीएफ 2023 में परिकल्पित है।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2023 से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व जिम्मेदार नागरिक नीति पर जोर।विज़न 2047 के आधार स्तंभों में शिक्षा की गुणवत्ता व जिम्मेदारनागरिक का महत्वपूर्ण रोल।संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि का विकसित भारत का सपना स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व जिम्मेदार नागरिक बनने पर निर्भर है,सटीक विश्लेषण है।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV
Drive the Future

ई-रिक्शा का किराया बढ़ेगा, लखनऊ परिवहन विभाग ने दरें तय कीं, क्षमता से अधिक यात्री बैठे तो होंगे सीज

परिवहन विशेष न्यूज

परिवहन विभाग ने पहली बार अन्य यात्री वाहनों की तरह ई-रिक्शा का किराया तय कर दिया है। यात्रियों को अब अधिकतम 8.30 रुपये प्रति किलोमीटर किराया देना होगा, क्योंकि अभी तक किराया मनमाना वसूला जा रहा था।

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वर लू ने अधिसूचना जारी कर बताया है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 67 की उपधारा एक के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य परिवहन प्राधिकरण ने अनुबंध वाहनों के रूप में संचालित ई-रिक्शा का अधिकतम किराया तय कर दिया है।

ई-रिक्शा का किराया अधिकतम 8.30 रुपये प्रति किलोमीटर होगा। प्रमुख सचिव ने परिवहन आयुक्त समेत अन्य को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य परिवहन प्राधिकरण के अध्यक्ष केपी सिंह ने बताया कि यह किराया पूरी ई-रिक्शा बुक होने के बाद ही देना होगा।

ई-रिक्शा में सवार प्रत्येक यात्री के लिए प्रति किलोमीटर किराया तय नहीं किया गया है। इस कदम से ई-रिक्शा का किराया बढ़ना तय है, क्योंकि अभी तक ई-रिक्शा संचालक प्रत्येक यात्री से 5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया वसूल रहे थे। चेयरमैन ने बताया कि पहले ई-रिक्शा के लिए प्रति किलोमीटर अधिकतम किराया तय नहीं था।

होंडा ने पेश की एक्टिवा e, 2025 से बेंगलुरु, नई दिल्ली और मुंबई में शुरू होंगे बैटरी स्वैपिंग स्टेशन

परिवहन विशेष न्यूज

हाल ही में होंडा एक्टिवा ई इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हुई है। इसमें स्वैपेबल बैटरी का फीचर दिया गया है। जिसके लिए कंपनी बेंगलुरु मुंबई और नई दिल्ली में बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने जा रही है। बेंगलुरु में फरवरी 2025 मुंबई और नई दिल्ली में अप्रैल 2025 से बैटरी स्वैपिंग स्टेशन शुरू हो जाएंगे। वहीं इसकी कीमतों का खुसाला जनवरी 2025 को होगा।

नई दिल्ली। होंडा ने हाल ही में भारत में एक्टिवा ई को लॉन्च किया है। इस स्कूटर में स्वैपेबल बैटरी दी गई है। इस बैटरी को आप घर पर चार्ज नहीं कर सकते हैं। जिसकी वजह से लोगों में इसकी चार्जिंग और रेंज की चिंता होने लगी है। इस चिंता को कम करने के लिए होंडा देश भर में बैटरी स्वैपिंग स्टेशन को स्थापित करने जा रही है। कंपनी इसे लगाने के लिए योजना बना रही है। आइए जानते हैं कि कहां पर कितने बैटरी स्वैपिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी।

तीन शहरों में लगेंगे बैटरी स्वैपिंग स्टेशन

होंडा टू-व्हीलर कंपनी भारत में एक्टिवा ई के लिए बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने के पहले चरण में तीन शहरों का चुनाव किया है, जो बेंगलुरु, मुंबई और नई दिल्ली है। होंडा की तरफ से घोषणा किया गया है कि बेंगलुरू शहर में बैटरी स्वैपिंग स्टेशन फरवरी 2025 से चालू हो जाएंगे और पूरे शहर में 250 स्वैपिंग स्टेशन होंगे। बेंगलुरू के बाद मुंबई और नई दिल्ली में इन्हें स्थापित किया जाएगा। यहां पर बैटरी स्वैपिंग स्टेशन अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएंगे और यहां पर क्रमशः 100 और 150 स्वैपिंग स्टेशन को लगाया जाएगा।

बैटरी स्वैपिंग स्टेशन के लिए इनसे पार्टनरशिप

होंडा ने 2021 में HEID (होंडा पावर पैक एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) की स्थापना की थी। HEID ने दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बैंगलोर मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, मुंबई में अदानी इलेक्ट्रिसिटी और शहरों में होंडा डीलरशिप के साथ पार्टनरशिप की है।

होंडा एक्टिवा E के फीचर्स

होंडा एक्टिवा ई में दो स्वैपेबल 1.5 kWh बैटरी दी गई हैं, जिसके बारे में होंडा का दावा है कि यह फुल चार्ज होने के बाद 102 किमी की रेंज देगी। इसमें लगा हुआ मोटर 6kW की पावर और 22Nm का पीक टॉर्क जनरेट करेगा। इसके साथ ही कंपनी दावा कर रही हैं कि उनकी यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 7.3 सेकंड में 0 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 80 किमी प्रति घंटा है।

होंडा के इलेक्ट्रिक स्कूटर में टेलिस्कोपिक फोर्क और मोनोशॉक दिया गया है और दोनों तरफ 12 इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं। इसमें आगे की तरफ 130 मिमी डिस्क ब्रेक और पीछे की तरफ 110 मिमी ड्रम ब्रेक दिया गया है। इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 171 मिमी और वजन 119 किलोग्राम है।

एक्टिवा इलेक्ट्रिक की आधिकारिक कीमत जनवरी 2025 में एलान की जाएगी।

दो ईवी टू-व्हीलर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई

परिवहन विशेष न्यूज

टू-व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों हीरो इलेक्ट्रिक और ओकिनावा के लिए बुरी और नकारात्मक खबर सामने आई है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इन दोनों कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। इन कंपनियों को फेम-2 नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया था, जिसके बाद इन दोनों ईवी कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। एसएफआईओ (SFIO) यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने इन दोनों कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। संगठन ने भारी उद्योग मंत्रालय की सिफारिश के बाद इन दोनों कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।

इन दोनों ईवी कंपनियों पर फेम-2 नियमों का उल्लंघन करने और फेम-2 सब्सिडी का दुरुपयोग करने का आरोप था। भारी उद्योग मंत्रालय ने इन्हें फेम-2 नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया था, जिसके बाद भारी उद्योग मंत्रालय की सिफारिश पर एसएफआईओ ने जांच शुरू कर दी है।

इसके अलावा आगे की जांच के लिए कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय को सिफारिश की गई है। एसएफआईओ ने हाल ही में दोनों कंपनियों पर छापेमारी की थी। अगर एसएफआईओ को भी कोई गड़बड़ी मिलती है तो पीएम ई-ड्राइव योजना से सब्सिडी का रास्ता बंद हो सकता है। इस खबर का दोनों कंपनियों पर बड़ा असर पड़ सकता है।

जी बिज़नेस को मिली खबर के मुताबिक अगर हीरो और ओकिनावा दोषी पाए जाते हैं तो इस मौके का फायदा ओला इलेक्ट्रिक को मिलेगा। अगर पीएम ई-ड्राइव सब्सिडी नहीं मिलती है तो इन कंपनियों के प्रोडक्ट ओला के ईवी स्कूटर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हीरो, ओकिनावा, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी एमसीए) और भारी उद्योग मंत्रालय ने ज़ी बिज़नेस के ई-मेल का जवाब नहीं दिया है।

एसएफआईओ ने फेम-II नियमों के उल्लंघनों के लिए गुरुग्राम में स्थित बहुचर्चित कंपनी के परिसर को किया सील

परिवहन विशेष न्यूज

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय ने फेम-II ईवी सब्सिडी मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए गुरुग्राम में हीरो इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड के परिसर को सील कर दिया है, जिससे कंपनी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, जो सिर्फ पांच साल पहले भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता हुआ करती थी।

कॉर्पोरेट धोखाधड़ी जांच एजेंसी के जांच निदेशक सुमित कसाना द्वारा 14 नवंबर को लिखे गए पत्र में कहा गया है, ₹यह नोटिस आपको यह सुनिश्चित करने के लिए दिया जा रहा है कि हीरो इलेक्ट्रिक वाहनों के नाम पर निर्मित उक्त सामान या अन्य सामान पर मेरे द्वारा लगाई गई सील बरकरार रखी जाए।₹ ₹कृपया ध्यान दें कि यदि निर्मित भवन को खोलने के समय सील बरकरार नहीं रखी जाती है, तो दंड प्रक्रिया संहिता में निर्धारित सभी परिणाम भुगतने होंगे।

मीडिया के अनुसार उद्योग विहार, सेक्टर 18 स्थित हीरो इलेक्ट्रिक की बिल्डिंग पर चिपकाए गए पत्र की एक प्रति देखी है। कॉरपोरेट धोखाधड़ी की जांच करने वाली एक वैधानिक एजेंसी एसएफआईओ, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत काम करती है।

इस मामले पर टिप्पणी के लिए मीडिया द्वारा हीरो इलेक्ट्रिक के प्रबंध निदेशक नवीन मुंजाल को किए गए फोन कॉल और व्हाट्सएप संदेशों के खबरों के प्रकाशित होने तक का कोई जवाब नहीं मिला।

हीरो इलेक्ट्रिक, जो पिछले चार साल से भी कम समय में बाजार में पैठ बना चुकी थी, वर्तमान समय मे कंपनी बुरी तरह से लड़खड़ा गई हैं। जांच एजेंसी में जब यह पाया गया कि कंपनी ने भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लान फेज-II के तहत स्थानीय खरीद और आयात मानदंडों का उल्लंघन किया है। इसका विनिर्माण संयंत्र एक साल से अधिक समय से बंद है। इसकी बाजार में हिस्सेदारी नगण्य हो गई है। डीलरों को बकाया भुगतान न करने के कारण कंपनी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अगस्त में हीरो इलेक्ट्रिक के कम से कम 200 डीलरों ने सैकड़ों करोड़ रुपये के बकाए की मांग करते हुए गुरुग्राम में कंपनी के मुख्यालय के बाहर डेरा डाल दिया था। इसमें 300 करोड़ रुपये का खाता शेष, 100 करोड़ रुपये का बकाया वारंटी खर्च और 150 करोड़ रुपये के अनबिके इलेक्ट्रिक स्कूटर शामिल हैं, जो बिना बैटरी या चार्जर के डिलीवर किए गए हैं।

दिल्ली में हीरो इलेक्ट्रिक डीलरशिप चलाने वाले निशांत बंसल ने मीडिया को जानकारी दी कि अभी तक कंपनी की तरफ से 10 रुपये भी नहीं चुकाए गए हैं। उन पर 60 लाख रुपये बकाया हैं और उनके पास बिना बैटरी और चार्जर के 60 स्कूटर हैं। कुल मिलाकर डीलरों के पास 1,500 स्कूटर का स्टॉक है।

2024 BMW M2 भारत में 1.03 करोड़ में लॉन्च, पहले ज्यादा पावरफुल इंजन समेत मिले नए कलर ऑप्शन

परिवहन विशेष न्यूज

2024 BMW M2 Launched अपडेट BMW M2 को भारतीय बाजार में 1.03 करोड़ रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है। इसमें इंजन पुराने मॉडल की तुलना में ज्यादा पावरफुल दिया गया है। इसमें 3-लीटर सिक्स-सिलेंडर इंजन है जो 480 PS की पावर जनरेट करता है। इसके अलावा नई BMW M2 को नए कलर ऑप्शन में लेकर आया गया है।

नई दिल्ली। BMW ने अपडेटेड M2 को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसे पूरी तरह से बिल्ट-अप यूनिट (CBU) के तौर पर भारत लाया जाएगा। इसकी कीमत मौजूदा मॉडल से 5 लाख रुपये ज्यादा है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 98 लाख रुपये थी। अपडेट मॉडल में एक्सटीरियर में मामूली बदलाव किया गया है। इसके साथ ही नए कलर ऑप्शन, अपग्रेडेड तकनीक और अपग्रेडेड पावरट्रेन भी दिया गया है। आइए जानते हैं कि 2024 BMW M2 किन खास फीचर्स के साथ लॉन्च हुई है।

2024 BMW M2: एक्सटीरियर

इसका एक्सटीरियर पहले जैसे मॉडल जैसा ही रखा गया है। इसके आगे और पीछे की तरफ BMW M2 का लोगो सिल्वर सराउंड के साथ काले रंग के साथ दिया गया है। इसके साथ ही आगे की तरफ किडनी ग्रिल में हॉरिजॉन्टल एलिमेंट भी दिए गए हैं।

इसमें एम कार्बन रूफ ऑप्शन में मिलता है, जो कोनों पर बेहतर कंट्रोल के लिए मददगार होता है। इसमें आगे की तरफ और पीछे की तरफ 19-इंजन के अलॉय व्हील और पीछे की तरफ 20-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसके ब्रेक कैलिप्स को मानक के रूप में ब्लू मैटेलिक शेड में फिनिश किया गया है, और ऑप्शनल रेड फिनिश भी दिया गया है।

नई BMW M2 को पोर्टिमाओ ब्लू, फ़ायर रेड, साओ पाउलो येलो और स्काईस्क्रेपर ग्रे नए मेटैलिक कलर ऑप्शन में लाया गया है। इसमें आपको ब्रुकलिन ग्रे और ब्लैक सैफायर मेटैलिक कलर भी दिया गया है। वहीं, गैर-मेटालिक शेड अल्पाइन व्हाइट और एम जैडवॉर्ट ब्लू ऑप्शन भी दिया गया है।

2024 BMW M2: इंटीरियर और फीचर्स

इसका इंटीरियर को फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील के साथ लाया गया है, जिसे ऑप्शनल अल्केन्टारा फिनिश दिया गया है। इसमें घुमावदार डिस्प्ले दिया गया है, जो 14.9-इंच का इंफोटेनमेंट और 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को 8.5 में अपडेट किया गया है। इसके सीटों को डुअल टोन रेड और ब्लैक कलर दिया गया है। वहीं, अंदर स्पोर्टी अपील के लिए एम कार्बन बकेट सीट का ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं।

नए BMW M2 में पैसेंजर की सेफ्टी के लिए कई एयरबैग, कई ड्राइवर एड्स, क्रूज़ कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट-स्टॉप फंक्शन, डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल और डायनेमिक ब्रेक कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

2024 BMW M2: इंजन

इसके इंजन को पुराने मॉडल की तुलना में ज्यादा पावरफुल बनाया गया है। नई BMW M2 में 3-लीटर छह-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो अब 480 PS (20 PS ज्यादा) की पावर और 600 Nm तक का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन या वैकल्पिक 6-स्पीड मैनुअल के साथ जोड़ा गया है।

नए M2 का इंजन 0.1 सेकंड तेज़ है। यह ऑटोमैटिक के साथ सिर्फ 4 सेकंड में और मैनुअल के साथ 4.2 सेकंड में 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है। वहीं, इसे ऑटोमैटिक के साथ 12.9 सेकंड और मैनुअल के साथ 13.7 सेकंड में 0-200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है। इसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इसे 285 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाया जा सकता है।

2024 BMW M2: कीमत

अपडेटेड BMW M2 की एक्स-शोरूम कीमत 1.03 करोड़ रुपये है। भारत में इसका सीधे तौर कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है।

महिला सशक्तिकरण के लिए पिंक ई-रिक्शा योजना ने गति पकड़ी

परिवहन विशेष न्यूज

पुणे की सड़कों पर एक बार फिर गुलाबी ई-रिक्शा दौड़ेंगे, क्योंकि महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने ई-रिक्शा परियोजना पर तेजी लाने का फैसला किया है।

इस योजना का उद्देश्य निम्न आय वर्ग की महिलाओं को वाहन उपलब्ध कराना है, जिसके माध्यम से वे आजीविका कमा सकें।

महाराष्ट्र ने चुनाव से पहले इस योजना की घोषणा की थी और अधिकारी चुनाव आचार संहिता हटने का इंतजार कर रहे थे।

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी मनीषा बिरारिस ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, ₹पुणे में करीब 275 महिलाओं ने पहले ही इसके लिए आवेदन भर दिए हैं। आदर्श आचार संहिता हटने के बाद हम और अधिक नामांकन के लिए जोर देंगे।"

बिरारिस ने कहा, ₹हम ई-रिक्शा के लिए मार्गों का पता लगाने के लिए जल्द ही पुणे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के साथ एक विस्तृत बैठक करेंगे।₹

ई-रिक्शा मुख्य रूप से उन मार्गों पर चलेंगे, जहां चार्जिंग की सुविधा है और अधिकारी महिला चालकों की सुरक्षा के पहलू पर भी विचार करेंगे।

आरटीओ के एक अधिकारी ने कहा, ₹जब 2016-17 में पहली बार पैसेंजर ई-रिक्शा शुरू किए गए थे, तो उन्हें चार्जिंग प्वाइंट की उपलब्धता और नियमित ऑटो चालकों के साथ किसी तरह की अनबन न हो, जैसे कई कारणों से नियमित ऑटोरिक्शा की तरह सभी मार्गों पर चलने की अनुमति नहीं दी गई थी। इस मामले में भी यही बात लागू होगी।

अधिकारी फिलहाल निश्चित मार्ग रखने की योजना बना रहे हैं।

अधिकारी ने कहा, ₹उदाहरण के लिए, अगर अंतिम मार्ग में से एक स्वर्गेट से डेक्कन है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि चालक उस सटीक स्थान पर नहीं जाएगा, जहां ग्राहक उसे ले जाना चाहता है। हम बस यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्ग निर्धारित और व्यस्त हों और उनमें उचित बुनियादी ढांचा हो।

पायलट परियोजना के लिए आठ जिलों को चुना गया है, पुणे, नागपुर, अमरावती, छत्रपति संभाजीनगर, अहिल्यानगर, कोल्हापुर, सोलापुर और नासिक।

एक अधिकारी ने बताया, ₹मानदंडों पर खरी उतरने वाली कुल 10,000 महिलाओं को ई-रिक्शा दिए जाएंगे। चुनाव के दौरान रुकी प्रक्रिया को तेज करने के लिए सभी आठ जिलों के कार्यालयों को निर्देश दिए गए हैं।

इस परियोजना को जल्द ही महाराष्ट्र के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा।

खिलाडियों को नौकरी नहीं, तो वजीफा दो

भूपिंद्र सिंह

हाल ही में आयोजित अखिल भारतीय अतंर राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सीमा ने पांच व दस मीटर की दौड़ों में रजत पदक जीते हैं। इस चैंपियनशिप में ही सेना में नौकरी कर रहे कांगड़ा के अंकेश ने आठ सौ मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीता है। सीमा, सावन, दिनेश व अंकेश आज राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सब एथलीटों को, जो हिमाचल से पलायन कर गए हैं, हिमाचल सरकार सम्मानजनक नौकरी दे तथा वजीफा भी दे

सरकारें प्रतिभाशाली खिलाडियों को सीधा वजीफा क्यों नहीं दे सकती हैं? हिमाचल प्रदेश के कुछ एथलीट हैं जो 2026 की एशियाई खेलों में देश के लिए खेल कर पदक दे सकते हैं। उनमें सावन और दिनेश सेना व सीमा भी राष्ट्रीय कैंप में रह कर राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ उभरते हुए जूनियर एथलीट हैं, जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले सत्र गोहाटी में आयोजित खेलो इंडिया अंतर विश्वविद्यालय एथलेटिक्स में राजकीय महाविद्यालय मंडी की धाविका कुसुम ठाकुर ने सौ मीटर की फर्राटा दौड़ में रजत व दो सौ मीटर में स्वर्ण पदक जीत कर हिमाचल का नाम रोशन किया है। हमीरपुर के सरकारी महाविद्यालय की धाविका प्रिय ठाकुर ने चार सौ मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीता है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की चार गुणा चार सौ मीटर दौड़ में भी लड़कियों ने कांस्य पदक जीता है। इस वर्ष पंजाब विश्वविद्यालय की एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हमीरपुर की मनीषा ठाकुर ने चार सौ मीटर की दौड़ को 53.1 सेकेंड में दौड़ कर स्वर्ण पदक जीता है। तेज गति की दौड़ों में हिमाचल के खिलाडियों का प्रदर्शन पहले कमजोर ही रहा है। यह अलग बात है कि पुष्पा ठाकुर ने जरूर इस मिथक को तोड़ कर भविष्य के एथलीटों को राह दिखाई है। मानव शरीर ईश्वर द्वारा बनाई गई बहुत ही अद्भुत मशीन है। इसे चलाने के लिए भी ईंधन की जरूरत होती है। मानव शरीर के ऊर्जा चक्र को समझने के लिए हमें एटीपी से लेकर सीपीए लैक्टिक एसिड, शरीर से ऑक्सीजन की उधारी व सांस द्वारा ऑक्सीजन का फेफड़ों में पहुंच कर खून के साथ मिलकर फिर सैल का पहुंच कर शरीर को गतिशील बनाए रखने का गहन अध्ययन जरूरी है।

सौ से लेकर चार सौ मीटर की दौड़ों को तेज गति में गिना जाता है। गति ही सभी स्पर्धाओं व खेलों की जीत का मूल मंत्र है। यह खिलाड़ी में जन्मजात होती है। प्रशिक्षण द्वारा भी इसमें बहुत ही कम एक उम्र तक विकास होता है। ओलंपिक खेलों में विभिन्न खेलों की कई स्पर्धाएं आयोजित होती हैं, मगर एथलेटिक्स का आकर्षण सबसे अधिक होता है। ओलंपिक में जो धावक सौ मीटर की दौड़ में विजेता बनता है, वह पृथ्वी का तीव्रतम इनसान बनता है। सौ मीटर की दौड़ का अद्भुत रोमांच होता है। हिमाचल प्रदेश में तेज गति के बहुत कम धावक व धाविकाएं आज तक सामने आए हैं। सौ मीटर से लेकर चार सौ मीटर की स्पर्धाओं को स्परिंट यानी तेज गति की दौड़ों में रखा है। इन स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए जहां जन्मजात स्पीड चाहिए होती है, वहीं पर बहुत अधिक स्पीड, इंडोरैंस व स्ट्रैंथ ट्रेनिंग की जरूरत होती है। जहां उच्च कोटि का प्रोटीन आम आदमी को असानी से उपलब्ध होता है, वहीं के लोगों में अच्छी स्पीड जन्म से ही होती है। स्पीड को बहुत छोटी उम्र से ही विकसित करना पड़ता है। इसलिए स्पीड पर प्रशिक्षण दस वर्ष से भी कम आयु में शुरू करना पड़ता है। अगले पांच सालों में स्पीड अपने उच्च स्तर तक विकसित हो जाती है। यह भी कहा जाता है कि स्परिंटर पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। भारत के अधिकतर स्परिंटर समुद्र तट से संबंध रखते हैं। मछली इन लोगों का मुख्य आहार है। मछली में अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन मिलता है। उत्तर भारत में शाकाहारी अधिक हैं, मगर गेहूं, दूध व उससे बने पदार्थों में भी अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन मिलता है। यह भी कारण है कि पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी समय-समय पर अच्छे स्परिंटर मिलते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश से वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पुष्पा ठाकुर ही एकमात्र धाविका है, जो हिमाचल प्रदेश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 400 मीटर में पदक विजेता है। एशिया व ओलंपिक खेलों के राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों तक पहुंचने वाली इस धाविका के बाद अभी तक कोई भी पुरुष या महिला हिमाचल प्रदेश के लिए वरिष्ठ राष्ट्रीय स्तर पदक जीत नहीं पाया है। भविष्य में उभरते हुए कुसुम, प्रिय व मनीषा आदि तेज गति के एथलीट हैं जिनको वजीफे की बहुत जरूरत है। इनके पास नौकरी नहीं है। सामान्य परिवारों से इनका संबंध है, जो इतना खर्च नहीं कर सकते हैं। लंबी दूरी की दौड़ों में हिमाचल का इतिहास अच्छा रहा है। सुमन रावत 1982 एशियाड में तीन हजार मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर अर्जुन अवार्डी है। स्वर्गीय कमलेश व अमन सैनी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हाल ही में आयोजित अखिल भारतीय अतंर राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सीमा ने पांच व दस मीटर की दौड़ों में रजत पदक जीते हैं। इस चैंपियनशिप में ही सेना में नौकरी कर रहे कांगड़ा के अंकेश ने आठ सौ मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीता है।

सीमा, सावन, दिनेश व अंकेश आज राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सब एथलीटों को, जो हिमाचल से पलायन कर गए हैं, हिमाचल सरकार सम्मानजनक नौकरी दे तथा इन सभी एथलीटों को 2026 खेलों तक वजीफा भी दे। इस स्तर पर अपना अभ्यास जारी रखने के लिए महीने में पचास हजार रुपए चाहिए होते हैं। जो नौकरी में हैं, वो तो बहुत कठिनाई से अपने वेतन से कुछ न कुछ जुगाड़ कर लेते हैं, मगर जो विद्यार्थी व बेरोजगार हैं, वे कैसे अपना अभ्यास जारी रखें, यह हिमाचल सरकार को सोचना होगा। क्या प्रदेश सरकार कुछ उपकार इन प्रतिभाशाली एथलीटों पर करेगी, ताकि वे फ्री माइंड होकर अपना प्रशिक्षण जारी रख सकें। खिलाड़ी बनाए नहीं जाते हैं, वे जन्म से ही अलग होते हैं। लाखों बच्चों में कोई एक प्रतिभाशाली एथलीट मिलता है। समाज व सरकार का दायित्व है कि वे भविष्य में देश को गौरव दिलाने वाले अति

संपादक की कलम से

किसान की गड्डी

यात्रा से आगे निकल कर हिमाचल पथ परिवहन निगम ने पहली बार किसान की मेहनत को अपनी बाहों का आसरा दिया। यानी अब सरकारी बसें मुफ्त में दूध-सब्जियां भी ढोएंगी। एचआरटीसी निदेशक मंडल की बैठक में एचआरटीसी अपने वजूद के तरन्नम में एक नया गीत सुनाने की कोशिश कर रही है, हालांकि निरंतर घाटे की सोहबत में सरकारी बसों का हुलिया डरा रहा है और इससे बाहर निकलने की कसमें या वादे दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहां हम यह जरूर कहना चाहेंगे कि एचआरटीसी मंडल तक हमारे कुछ सुझाव दर्ज हुए हैं और उन्हीं की लिखावट में मॉल सरीखे बस स्टैंड बनाने की परिकल्पना साकार होने जा रही है। मंडी, भराड़ी और बिलासपुर के बस स्टैंड अगर कल के मॉल की तर्ज पर विकसित होने जा रहे हैं, तो ये आमदनी के नए स्रोत होंगे। एचआटीसी अपनी क्षमता का निरूपण अगर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप या सीधे निजी निवेश के जरिए करे, तो मौजूदा संपत्तियों से ही आय के कई स्रोत निकल आएंगे। लेकिन सियासत के सदर्भों को छोडक़र स्वतंत्र फैसले लेने होंगे। मसलन दस-बारह सालों से धर्मशाला का प्रस्तावित बस अड्डा अगर अपने बनने की खाक छान रहा है, तो इसे महज सियासत ही कहना होगा, वरना पर्यटक स्थलों में एचआरटीसी के मुकाबले निजी वोल्वो बसें इस कद्र हावी न होतीं। आश्चर्य यह भी कि सरकारी वोल्वो बसों की खरीद हर बार निदेशक मंडलों के लफ्जों में ही बयां होती है, जबकि यथार्थ में बूढ़ी हो चुकी बसें केवल 'फेरा' ही लगा रही हैं। करीब दो साल से हिमाचल को हरित राज्य बनाने का कैरियर बनी एचआरटीसी के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों का इंतजार कब खत्म होगा, इसके बारे में निदेशक मंडल ने पुनः 327 बसों की हामी भरी है।

कुछ भर्तियां निचले स्तर पर एचआरटीसी के संचालन को मजबूत करने की राह पर प्रस्तावित हैं, तो नए बस स्टैंड्स के खाते में ढली और ठियोग में सौगात बनकर खुल रही हैं। इसी के साथ नए बस अड्डों को जमीन खोदते इरादे कह रहे हैं कि कल बद्दी, भोटा, सुजानपुर, फतेहपुर व नौहराधार में भी अपने परिसर होंगे। दरअसल पथ परिवहन निगम अगर अपनी क्षमता और छवि को दुरुस्त करे, तो हिमाचल वाकई पर्यटन राज्य बन सकता है। अंतरराज्यीय रूट समझौतों में पर्यटन की क्षमता टिकी है। कहने को तो बसें अयोध्या राम मंदिर के लिए भी निकली, लेकिन वे पर्यटकों को नहीं पहुंचा पाईं। ऐसा क्यों है कि राज्य से दिल्ली व हरिद्वार तो अब पर्यटक रूट बन गए, लेकिन अमृतसर, जयपुर व कटड़ा नहीं बन सके। अगर सरकारी बसों के रूट पर्यटन की जरूरतों को समझें तो राज्य के भीतर भी विभिन्न मंदिरों के दर्शन, हवाई अड्डों व रेलवे स्टेशनों से मुख्य शहरों के लिए स्थायी, सुविधाजनक व सस्ती बस सेवाएं शुरू हो सकती हैं। एलायंस एयरलाइन ने शिमला से धर्मशाला की हवाई टिकट मात्र 1714 रुपए में कर दी। अगर इसके साथ शिमला से जुब्बड़हट्टी व गगल हवाई अड्डे से धर्मशाला, मकलोडगंज, पालमपुर व हमीरपुर के लिए एचआरटीसी के टैंपो ट्रैवलर्स भी जुड़ जाएं, तो प्रदेश का पर्यटन उद्योग नई मंजिल पर खड़ा होगा। एचआरटीसी की सेवाओं को सुधारने के टैक्सी उद्योग के चरित्र को भी सही करना पड़ेगा। दरअसल एचआरटीसी के पास हिमाचल परिवहन के हर मजमून का हल होना चाहिए। मात्र बसें नहीं, बल्कि छोटे वाहनों के संचालन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। हिमाचल परिवहन का पूर्ण मार्गदर्शन का जिम्मेदारी का दायित्व ओढने के लिए नए सिरे से विचार तथा कार्यशैली में परिवर्तन की जरूरत है।

ईवीएम का भूत

महाराष्ट्र चुनाव में करारी पराजय के बाद कांग्रेस और उसके कुछ सहयोगी दलों ने चीखना शुरू कर दिया है-ईवीएम में भूत है, जो भाजपा को ही वोट भेजता है।' अब विपक्षी राग इतना उग्र हो चुका है कि राहुल गांधी की 'बैलेट पेपर यात्रा' की खबर सुर्खियों में है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े ने भी कहा है कि बैलेट पेपर की वापसी के लिए हमें अब आंदोलन करना चाहिए। यह कांग्रेस की संवैधानिक इच्छा है कि वह 'ईवीएम बनाम बैलेट पेपर' का जनांदोलन शुरू करे, लेकिन भारत के चुनाव आयोग को यूं ही नहीं कोसा जा सकता। चुनाव आयोग की स्थापना संविधान लागू होने से पूर्व ही कर दी गई थी। संविधान और लोकतंत्र की गरिमा और सफलता तभी है, जब देश में स्वतंत्र, निर्भीक, मुक्त और निष्पक्ष चुनाव हों। संविधान सभा में चुनाव आयोग के प्रारूप पर लंबी बहसें हुई थीं। उन्हीं के बाद संविधान में चुनाव आयोग तथा चुनाव प्रक्रिया से संबंधित 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे। उनमें बुनियादी अनुच्छेद 324 भी शामिल था। अब इन तर्कों के कोई भी मायने नहीं रहे कि कांग्रेस जब किसी राज्य में अथवा लोकसभा चुनाव में 100 सीटें जीतती है, तो ईवीएम का भूत 'कांग्रेसमय' हो जाता है। जब हरियाणा और महाराष्ट्र सरीखे महत्वपूर्ण चुनाव हारती है, तो फिर 'भाजपा का भूत' चिल्लाने लगती है। हालांकि झामुमो-कांग्रेस गठबंधन ने झारखंड का चुनाव जीता है और वहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शपथ भी ग्रहण कर चुके हैं। कांग्रेस के ईवीएम पूर्वाग्रह और भूतैले आरोपों पर सर्वोच्च अदालत ने हाल ही में फटकार लगाई है। सर्वोच्च अदालत ईवीएम को दोषमुक्त मानते हुए 'हरी झंडी' भी दे चुकी है। सवाल यह है कि चुनाव आयोग कांग्रेस समेत विपक्ष को आश्वस्त कैसे करे कि ईवीएम में कोई भूत नहीं है, उसे हैक नहीं किया जा सकता अथवा ईवीएम में विसंगतियां नगण्य हैं? अ

ब कांग्रेस ईवीएम के बजाय 'बैलेट पेपर' से मतदान कराने पर अड़ी है। चुनाव-प्रक्रिया के 'पाषाण-काल' में लौटने की जिद की जा रही है। बैलेट पेपर से मतदान वाले दिन और दौर हमने भी देखे हैं। कब, कितने बूथ लूट लिए गए अथवा अवैध मतदान किया गया, अवैध बूथ छाप दिए गए या मतदान से पहले ही 'बैलेट पेपर' लीक हो गए और घरों पर बैठ कर उन पर मुहर लगा दी गई? ऐसे असंख्य दृश्य बिहार, उप्र, पश्चिम बंगाल चुनावों के हमें आज भी याद हैं और कौंधते रहते हैं। कांग्रेस ने अधिकतर चुनाव बैलेट युग में ही जीते हैं। क्या अब देश को भी पाषाण-काल में लौट जाना चाहिए? ईवीएम 2004 से भारत में लागू है। तब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी। अगला 2009 का आम चुनाव भी कांग्रेस के पक्ष में रहा था, हालांकि किसी भी पक्ष को बहुमत हासिल नहीं हुआ था। भारत की चुनाव-व्यवस्था विश्व भर में विख्यात और प्रशंसनीय है। बीते 12 सालों से 130 से ज्यादा देशों के चुनाव आयुक्त हमारे चुनाव आयोग से सीख रहे हैं। इतना व्यापक मतदान देख कर और उसकी प्रक्रिया जान कर वे विदेशी आयुक्त अचंभित होते हैं। क्या अच्छी तरह चुनाव सम्पन्न कराना 'महान लोकतंत्र' का हिस्सा नहीं है? बेशक हमारे चुनावों पर भ्रष्टाचार, अनपढ़ता, खराब लैंगिक भागीदारी, नागरिक मुक्ति पर हमले और देश की राजनीतिक संस्कृति सरीखे कुछ कलंक भी चस्पा किए जाते रहे हैं। बहरहाल अब मुद्दा ईवीएम का है। सर्वोच्च अदालत और चुनाव आयोग 'बैलेट पेपर मतदान' की संभावनाओं को खारिज कर चुके हैं। ऐसा करना व्यावहारिक नहीं होगा।

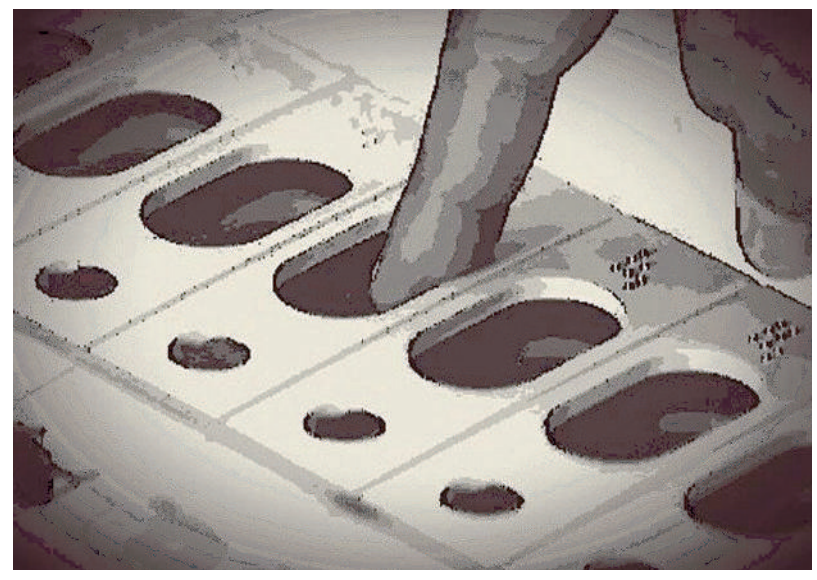

गुरु गोबिंद सिंह जी के दक्षिण भ्रमण का फल

आक्रमणकारी कौन थे? किसलिए गुरु जी को मारना चाहते थे? इस सम्बन्ध में इतिहासकारों में मतभेद पाया जाता है, परन्तु प्राय: कहा जाता है कि पठान सरहिन्द के नवाब ने गुरु जी की हत्या के लिए भेजे थे। देहावसान के समय गुरु जी की आयु 42 वर्ष की थी और विक्रमी 1765 की शुचि पंचमी थी। गुरु गोबिंद सिंह जी के दक्षिण प्रयाण से भारतीय इतिहास ने नई करवट ली। उन्होंने बंदा बैरागी को जो सीख दी, उससे बंदा बैरागी ने स्वाधीनता के संघर्ष का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया, जो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है। इसी तरह गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान भी भारतवासियों को सीख देता है। बलिदानों की यह परंपरा गुरु गोबिंद सिंह जी ने जारी रखी

खिदराणा के युद्ध के बाद गुरु जी भ्रमण करते-करते तलवण्डी साबो पहुंचे। इस स्थान पर गुरु जी कुछ देर के लिए स्थायी रूप से रहे। गुरु जी का यह निवास साहित्यिक दृष्टि से अत्यन्त महत्व रखता है। गुरु ग्रन्थ का आज जो रूप उपलब्ध होता है, उसे वर्तमान रूप यहीं दिया गया था। इसी स्थान पर से गुरु जी ने औरंगजेब को दक्षिण में एक पत्र लिखकर भेजा जो जफरनामा के नाम से प्रसिद्ध है। भाई व्यासिंह के हाथ जफरनामा औरंगजेब के नाम प्रेषित करके गुरु जी पंजाब से दक्षिण की ओर चल पड़े। मार्ग में ही उन्हें औरंगजेब की मृत्यु की सूचना मिली। औरंगजेब की मृत्यु ने स्थिति को एकदम बदलकर रख दिया। अतः गुरु जी तुरन्त दिल्ली की ओर चल पड़े। औरंगजेब की मृत्यु के उपरान्त उसके पुत्रों मुअज्जम तथा आजम में सत्ता प्राप्ति के लिए युद्ध की तैयारियां होने लगीं। औरंगजेब का ज्येष्ठ पुत्र मुअज्जम गुरु जी का पूर्व परिचित था। उसने गुरु जी से सहायता की प्रार्थना की। गुरु जी ने उसे विजय का आश्वासन तो दिया लेकिन सैनिक सहायता दी या नहीं, इसका निश्चित प्रमाण नहीं मिलता। अस्तु दोनों भाईयों का आगरे के निकट जमकर युद्ध हुआ और मुअज्जम बहादुरशाह के नाम से गद्दी पर बैठा। इस सारे कांड के बाद गुरु जी दिल्ली से आगरे की ओर चल पड़े और वहीं रहकर धर्म प्रचार करने लगे। बहादुर शाह ने एक दिन गुरु गोबिंद सिंह जी को मिलने के लिए बुलाया और एक मूल्यवान खिलअत, एक घुगधुगी और एक कलगी भेंट की। गुरु जी आगरे में टिके रहे। 1707 को बहादुर शाह राजपूतों का विद्रोह दबाने के लिए राजस्थान की ओर चल दिया और वहीं से दक्षिण में अपने छोटे भाई के विद्रोह को कुचलने के लिए दक्षिण की ओर चल दिया। कुछ समय के बाद गुरु जी नान्देड़ पहुंच गए। नान्देड़ में रहते हुए गुरु जी को एक महन्त-वैरागी के बारे में पता चला, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने जिन्न भूत अपने अधीन में किए हुए हैं। गुरु जी उस विलक्षण व्यक्ति को देखने उसके डेरे पर गए। बैरागी बाहर गया हुआ था।

गुरु जी उसके आसन पर बैठ गए। बैरागी ने बाहर से आकर गुरु जी को आसन से गिराने के लिए तान्त्रिक विद्या के अनेक प्रयोग किए, लेकिन सफलता न मिली। वह गुरु जी के चरणों पर गिर पड़ा। गुरु जी ने उसे कर्म का उपदेश दिया। मातृभूमि की दयनीय अवस्था का चित्रण किया। विदेशियों के अत्याचारों से अवगत कराया। बैरागी पर इसका अद्भुत प्रभाव पड़ा। गुरु जी ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाकर अपने कार्य को बढ़ाने के लिए पंजाब भेजा। यही साधु आगे चलकर बन्दावैरागी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नान्देड़ पहुंचने के एक मास उपरान्त ही गुरु जी का देहावसान हो गया। गुरु शौर्य में लिखा है- कि एक पठान कुछ दांव लेकर प्रभु के पास आया और दो-तीन घड़ी वहां बैठा रहा, परन्तु उसका दांव न लगा क्योंकि वहां बहुत लोग उपस्थित थे। उस दिन वह चला गया और दूसरे दिन फिर आया। उस दिन भी वह दो-तीन घड़ी बैठकर घात लगाता रहा, परन्तु उस दिन भी उसे सफलता नहीं मिली, और वह घर चला गया। इस प्रकार वह कई दिन आता रहा। परन्तु उसका दांव न लगा। परन्तु अनेक बार आने के कारण उसने इस भेद का पता पा लिया कि उसके काम का समय संध्या का है। वह दुष्ट एक दिन शाम के समय आया। गुरु जी ने उसे निकट बुलाया और अपने पास बैठाकर प्रसाद दिया, जिसे उस दुष्ट ने हाथ में लेकर मुंह में डाल लिया। उस समय वहां कोई सिंह नहीं था। केवल एक रक्षक था, वह भी ऊंघ गया था। इतने में प्रभु स्वयं विश्राम करने लगे। अवसर देखकर उस पठान ने उन पर छुरे से आक्रमण कर दिया। उसने उन पर दो वार किए कि गुरु जी ने निकट रखी अपनी तलवार के एक ही वार से उस दुष्ट को वहीं मार गिराया। फिर उन्होंने आवाज देकर शिष्यों को बुलाया। झटपट बहुत से लोग वहां आ गए और उसके दो साथियों को जो डेरे से बाहर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, मार डाला। डेरे के अन्दर पड़े तीसरे पठान के शव को देखकर सिक्ख उस पर तलवार चलाने ही वाले थे कि गुरु जी ने कहा, यह तो कभी का मर चुका, इसे यहां से हटाओ। अभी तक किसी को यह पता नहीं लगा था कि गुरु स्वयं जख्मी हो गए हैं।

परंतु जब वे उठे और लडख़ड़ाए, तब उन्हें इस दुःखद घटना का पता लगा और वे दुःख में डूब गए। गुरु ने सबको सान्त्वना दी कि भय की कोई बात नहीं है। अकाल ने उनकी रक्षा की है। इसी समय घाव धोकर सी दिए गए। परन्तु जब उन्होंने उठने का प्रयास किया तो धागे टूट गए। घाव फिर सी दिए गए और उन पर मरहम लगा दी गई। तीन-चार दिन व्यतीत हुए। बहुत से सिक्ख उनके दर्शन के लिए आ रहे थे। उनकी प्रार्थना पर गुरु जी दरबार में आए। फिर कुछ दिन व्यतीत हुए। सिक्खों में आनन्द छा गया। परन्तु वे समझ गए थे कि उनका अन्त समय निकट आ गया है। एक रात्रि को थोड़ा भोजन करके वे लेट रहे थे। आधी रात से चार घड़ी समय अधिक व्यतीत हुआ कि उन्होंने सब सिक्खों को बुलाया। सभी सिक्ख उनके निकट एकत्र हो गए और गुरु गोबिन्द सिंह जी ने उनसे अन्तिम बार 'वाहि गुरु जी की फतेह' कही और उनकी आत्मा ने अपनी नश्वर देह को छोड़ दिया। आक्रमणकारी कौन थे? किसलिए गुरु जी को मारना चाहते थे? इस सम्बन्ध में इतिहासकारों में मतभेद पाया जाता है, परन्तु प्राय: कहा जाता है कि पठान सरहिन्द के नवाब ने गुरु जी की हत्या के लिए भेजे थे। देहावसान के समय गुरु जी की आयु 42 वर्ष की थी और विक्रमी 1765 की शुचि पंचमी थी। गुरु गोबिंद सिंह जी के दक्षिण भ्रमण से भारतीय इतिहास ने नई करवट ली। उन्होंने बंदा बैरागी को जो सीख दी, उससे बंदा बैरागी ने स्वाधीनता के संघर्ष का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया, जो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है। इसी तरह गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान भी आज भी भारतवासियों को सीख देता है। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं।

बलिदानों की यह परंपरा जारी रखते हुए उनके पुत्र गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी भारतीय समाज, हिंदू धर्म और भारतीय राष्ट्र के लिए काफी कुछ किया। उनके दो पुत्र मुगलों से लड़ाई में शहीद हो गए, तो दो को जिंदा ही दिवारों में चिनवा दिया गया। राष्ट्र के लिए, भारत के लिए, भारतीय समाज के लिए, और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए यह बलिदान सचमुच ही अविस्मरणीय है। पहले सिख गुरु, गुरु नानक देव जी ने जहां सिक्ख धर्म की स्थापना की, वहीं उन्होंने लंगर प्रथा को भी शुरू करवाया, ताकि समाज में समानता का भाव बना रहे, एकता बनी रहे। दूसरे गुरु, गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी का विकास किया। तीसरे गुरु, गुरु अमर दास जी ने जातपात तथा पर्दा प्रथा का विरोध किया। गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की। गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया और स्वर्ण मंदिर की स्थापना की। गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने सिखों को लड़ाका कौम बनाया। सार यह है कि सभी गुरुओं ने भारत भूमि की अतुलनीय सेवा की।

भारत मे गणित विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता - विजय गर्ग

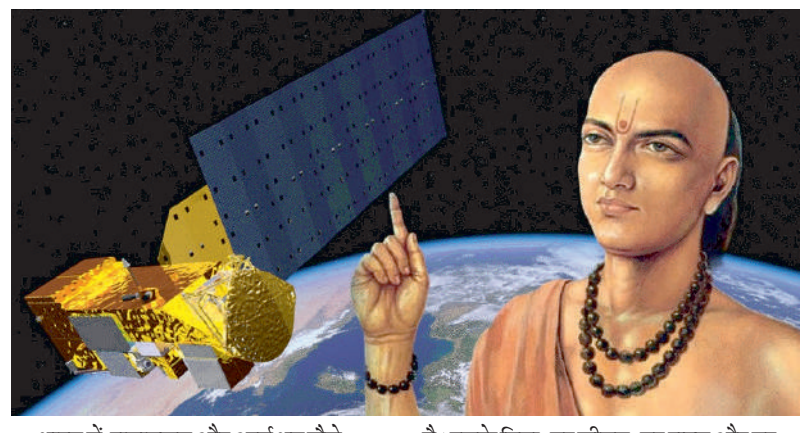

भारत में रामानुजन और आर्य भट्ट जैसे महान गणितक पैदा हुए हैं। भारत में विभिन्न गणितीय शोध की पहचान रामानुजन और आर्य भट्ट ने दिलवायी है। कुछ छात्र इस विषय में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। वे एक उबाऊ और कठिन, जटिल विषय मानते है।

केवल छात्र ही नही शिक्षकों भी विषय को पहले मुश्किल मानते है। गणित विषयों प्रेरित करने के लिए गणित विषयों के बारे में छात्रों को ज्ञान दे , उसके तत्वों के बारे में , गणित के पाठ्यक्रमों, गणित क्षेत्र में नौकरियों और रोजगार के अवसर बहुत महत्वपूर्ण है। गणित विषयों और छात्रों के लिए इसके महत्व के लिए गणित महीने मे गणित सप्ताह, गणित जश्न मनाने की जरूरत है।

संबंधित गणित विषयों बुद्धिजीवी, विशेषज्ञों, प्रासंगिक गणित सामग्री, गणित, साहित्य और गणित विश्वविद्यालय के अलग निर्माण से गणितीय तत्वों एक ही जगह में उपलब्ध करावाया जाए ।गणित के तरीके आसान और दिलचस्प बनाने के लिए के लिए खोज की जाए। गणित के अनुसंधान काफी हद तक जरूरी है। कुछ एक बदलाव करने की जरूरत है। गणित की आज बहुत अधिक मांग है। इसके बिना, हर जीवन, हर राज्य और हर देश अधूरा है। पुस्तकों को विशेषज्ञों से मिलकर बीजगणित ,त्रिकोणमिति को आसान बनाना चाहिए ।बच्चों को वास्तविक मे गणित पढ़ने का उद्देश्य पता नहीं है। ।विश्वविद्यालय को समय-समय पर छात्रों को मार्गदर्शन करने के स्कूलों और कॉलेजों मे अपने विशेषज्ञों को भेजना चाहिए ।

10 वीं कक्षा तक गणित सरल और मूल भाषा मे है। लेकिन 11th मे विषय पाठ्यक्रम के रूप में, नए क्षेत्र और विदेशी भाषा में छात्रों अक्सर होल्ड खो रहे है। लेकिन हर संभव तरीके से बुद्धिजीवियों की गरिमा बनाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। समय हमेशा बदलता है। इस बदलाव में पूर्ण भूमिका सरकार की होनी चाहिए ।पहले से ही चिकित्सा विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, की स्थापना के रूप मे हो चूकी है। गणित विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए ।इसके बारे मे सरकार को मूलरूप में पूरा विचार करना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार को गणित विश्वविद्यालय की स्थापना की पहल करनी चाहिए।

जेब पर डाका, इकोनॉमी के लिए खतरा; आखिर साइबर क्राइम पर कैसे लगेगी

परिवहन विशेष न्यूज

देश में बढ़ते डिजिटलीकरण के साथ साइबर अटैक के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। इस साल के पहले नौ महीनों में साइबर फ्रॉड की वजह से 11333 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। एक्सपर्ट का मानना है कि अपराध पर लगाम नहीं लगी तो 2033 तक हर साल भारत में सालाना एक लाख करोड़ साइबर अटैक होंगे। इनमें डेटा चोरी रैनसमवेयर साइबर बुलिंग जैसी कई चीजें शामिल हैं।

नई दिल्ली। इन दिनों साइबर अपराध अखबार की सुर्खियों में है। कभी सेक्टॉर्शन के नाम पर तो कभी ऑनलाइन फ्रॉड के नाम पर रोजाना लाखों-करोड़ों रुपये का फ्रॉड हो रहा है। आलम यह है कि हर अज्ञात कॉल को लोग शक की निगाह से देखने लगे हैं। आंकड़े भी चौंकाने वाले ही हैं। गृह मंत्रालय से जुड़ी एजेंसी सिटिजन फाइनेंशियल साइबर फ्राड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम (सीएफसीएफआरएमएस) के मुताबिक वर्ष 2024 में नवंबर माह तक साइबर फ्राड की लगभग 12 लाख शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं।

साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर के आंकड़े बता रहे हैं कि इस साल के पहले नौ महीनों में साइबर फ्रॉड की वजह से 11,333 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। पब्लिक रिस्पांस अगेंस्ट हेल्पलेसनेस एंड एक्शन फॉर रिड्रेसल (प्रहार) का मानना है कि अपराध पर लगाम नहीं लगी तो वर्ष 2033 तक हर साल भारत में सालाना एक लाख करोड़ साइबर अटैक होंगे।

साइबर अटैक में कौन-सी चीजें शामिल

साइबर अटैक में ऑनलाइन फ्राड और सेक्सटॉर्शन जैसी चीजें ही शामिल नहीं हैं। इनमें डेटा चोरी, रैनसमवेयर, ऑनलाइन हेट क्राइम, साइबर बुलिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सेवाओं पर साइबर अटैक, आइडेंटिटी थेफ्ट, अवैध बेटिंग (सट्टेबाजी) ऐप जैसी कई चीजें शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल किसी देश की आर्थिकी व आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करने में किया जा सकता है।

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ व भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी मुक्तेश चंदेर का कहना है कि साइबर अटैक का इस्तेमाल किसी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत कड़ी को कमजोर करने में हो सकता है। एस्टोनिया में हमने ऐसा देखा है। प्रहार के राष्ट्रीय संयोजक अभय मिश्रा के मुताबिक साइबर अटैक किसी देश की आंतरिक सुरक्षा व उनकी आर्थिकी को कमजोर करने का टूल बनता जा रहा है।

साइबर अपराध रोकना किसकी जिम्मेदारी?

इस साल अगस्त में संसद सत्र के दौरान गृह मंत्रालय ने बताया था कि अन्य अपराध की तरह साइबर फ्रॉड को रोकना भी राज्य की एजेंसियों की जिम्मेदारी है। साइबर अपराध से निपटने के तंत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र ने साइबर क्राइम कोर्डिनेशन सेंटर के साथ नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की स्थापना की है। इसके अलावा साइबर अपराध को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है।

इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय साइबर अपराध पर लगाम के लिए पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर चल रहे साइबर अपराध को रोकने के लिए देश में अभी अलग से कोई विशेष कानून नहीं है। आईटी एक्ट में संशोधन के तहत 2022 में लाए गए प्रविधानों के तहत ही साइबर अपराध को रोकने की अभी कोशिश की जा रही है।

आईटी एक्ट में मुख्य रूप से डेटा चोरी रोकने, इंटरमीडियरीज और ऑनलाइन इंटरनेट प्लेटफॉर्म को देश से बाहर डेटा नहीं भेजने और साइबर सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करने, आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने जैसे प्रविधान है।

साइबर अपराध पर कैसे लगेगी लगाम?

साइबर कानून के विशेषज्ञ सुप्रीम कोर्ट के वकील पवन दुग्गल कहते हैं कि रोजाना हो रहे डिजिटल अरेस्ट एवं अन्य वित्तीय फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार को एक बहुमुखी रणनीति बनानी होगी। साइबर अपराध के लिए समर्पित कानून की जरूरत है। अलग-अलग सेक्टर के हिसाब से साइबर कानून बनाना होगा। बैंक में साइबर अपराध का तरीका अलग होगा तो किसी व्यक्ति विशेष के साथ अलग।

दुग्गल ने बताया कि आईटी एक्ट के 2022 के प्रविधानों के मुताबिक साइबर अपराध होने के छह घंटे के भीतर सरकारी नोडल एजेंसी को रिपोर्ट करने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। निजी सेक्टर को भी साइबर सुरक्षा बहाल करने में भागीदार बनाना होगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्र की पहल पर राज्यों में अलग से साइबर पुलिसिंग की व्यवस्था की जरूरत है। केंद्र की तरफ से साइबर आर्मी बनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि सैटेलाइट पर होने वाले अटैक को बचाया जा सके। रूस व चीन इस दिशा में काम कर रहे हैं।

मोदी सरकार का रोजगार पर बढ़ा फोकस, 1 करोड़ से अधिक नौकरियां देने का प्लान

केंद्र सरकार की ओर से बीते चार महीने के दौरान 4.19 लाख करोड़ के बुनियादी ढांचे की बड़ी परियोजनाओं की मंजूरी दी गई। इससे केवल वैश्विक स्तर का ढांचागत निर्माण ही नहीं होगा बल्कि लाखों की संख्या में नौकरियों-रोजगार के अवसर युवाओं को मिलेंगे। सरकार का आकलन है कि हर 4.1 करोड़ रुपये के ढांचागत पूंजी निवेश पर चार से छह नौकरियां सृजित होंगी।

नई दिल्ली। रोजगार पर निरंतर गरम सियासत के बीच मोदी 3.0 सरकार ने बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश के जरिए रोजगार सृजन की गति तेज कर दी है। केंद्रीय कैबिनेट की ओर से पिछले चार महीने में 4.19 लाख करोड़ के बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं की मंजूरी के साथ ही अगले पांच साल में करीब 1.26 करोड़ नौकरियों के सृजन का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

सरकारी भर्ती प्रक्रिया की गति भी बढ़ने लगी है और पिछले चार महीनों के दौरान केंद्र सरकार के मंत्रालयों-विभागों में 60 हजार से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं। रोजगार के मोर्चे पर केंद्र सरकार से जुड़े तमाम महकमों की यह गति इसलिए भी बढ़ी कि आम बजट 2024-25 में दो लाख करोड़ रूपए के जरिए अगले पांच साल में चार करोड़ रोजगार का निर्माण करने का लक्ष्य हासिल करना भी है।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट की ओर से बीते चार महीने के दौरान 4.19 लाख करोड़ के बुनियादी ढांचे की बड़ी परियोजनाओं की मंजूरी दी गई। इससे केवल वैश्विक स्तर का ढांचागत निर्माण ही नहीं होगा, बल्कि लाखों की संख्या में नौकरियों-रोजगार के अवसर युवाओं को मिलेंगे। सरकार का आकलन है कि हर 4.1 करोड़ रूपए के ढांचागत पूंजी निवेश पर चार से छह नौकरियां सृजित होंगी।

रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना के तहत 3.39 करोड़ लोगों को लाभ होगा। सरकारकी ओर से संसद में घोषित पीएम इटर्नशिप के तहत एक करोड़ युवाओं को शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के साथ ही भत्ते और एकमुश्त सहायता भी मिलेगी। वहीं देश के 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान कर उन्हें उद्योग-बाजार की मांग के हिसाब से रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा।

खास बात यह भी है कि रोजगार-नौकरियों के सृजन की निगरानी करने वाले सरकारी महकमे में भी खाली पदों को भरने की गति दी गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और ईएसआईसी में बीते चार महीने में 4300 से अधिक युवाओं को सरकारी पदों पर नियुक्ति का पत्र जारी किया जा चुका है और 5000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।

केंद्रीय कैबिनेट ने हाल में ढांचागत विकास की जिन बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है उसमें महाराष्ट्र के वधावन में 76,220 रुपए के खर्च से एक बड़े बंदरगाह का विकास खास है क्योंकि अकेले इससे 12 लाख नौकरियों के सृजन का अनुमान है। साथ ही 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरों से 40 लाख नौकरियों का सृजन होगा।

गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी) के विकास से 22,000 नौकरियों के अवसर बनेंगे। जबकि चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना चरण के दूसरे चरण के दौरान 9000 कुशल और 7500 अर्ध-कुशल रोजगार सृजित होंगे। इसके साथ ही कृषि ढांचागत विकास, पीएम-ड्राइव से भी लाखों रोजगार के अवसर आने वाले समय में युवाओं को मिलेंगे।

डिलीवरी बॉय को भी मिलेगी ईपीएफओ से पेंशन? श्रम मंत्रालय बना रहा योजना

श्रम मंत्रालय गिग वर्कर्स को रिटायरमेंट की उम्र में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में काम कर रहा है। श्रम मंत्रालय का मानना है कि एग्रीगेटर कंपनियों में काम करने वाले गिग वर्कर्स का वेतन सीमित है और ऐसे में उनके वेतन के हिस्से से योगदान लेकर पेंशन देना मुनासिब नहीं होगा। एग्रीगेटर कंपनियों को अपने सालाना लाभ का एक हिस्सा गिग वर्कर्स के पेंशन फंड में देना चाहिए।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सर्विस डिलीवरी क्षेत्र में काम कर रहे लाखों गिग वर्कर्स को रिटायरमेंट की उम्र में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन का प्रबंध करने के लिए हितधारकों से चर्चा की पहल शुरू कर दी है। श्रम और रोजगार मंत्रालय इस दिशा में गिग वर्कर्स को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के जरिए पेंशन के दायरे में लाने के लिए सेवा क्षेत्र में काम कर रही सभी बड़े एग्रीगेटर कंपनियों से चर्चा कर रहा है।

गिग वर्कर्स को पेंशन देने के लिए श्रम मंत्रालय और EPFO एग्रीगेटर कंपनियों से अपने सालाना लाभ का एक फीसद हिस्सा पेंशन फंड में देने के लिए राजी करने जैसे विकल्पों पर गौर करने की पहल में जुटे हैं। सेवा क्षेत्र के निरंतर बढ़ते आकार के बीच देश में गिग वर्कर्स की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ रही है और सरकार ऐसे में इस क्षेत्र में काम करने वालों को सामाजिक सुरक्षा के कवच में लाए जाने की जरूरत महसूस कर रही है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, इसके मद्देनजर ही श्रम मंत्रालय और EPFO ने गिग वर्कर्स को रिटायरमेंट की उम्र से पेंशन दिए जाने के लिए सभी हितधारकों से चर्चा शुरू की पहल शुरू की है। इस क्रम में स्विगी, जोमैटो जैसी कुछ बड़ी एग्रीगेटर कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन से चर्चा की गई है।

बताया जाता है कि इन चर्चाओं के दौरान श्रम मंत्रालय की राय थी कि एग्रीगेटर कंपनियों में काम करने वाले गिग वर्कर्स का वेतन सीमित है और ऐसे में उनके वेतन के हिस्से से योगदान लेकर पेंशन देना मुनासिब नहीं होगा। एग्रीगेटर कंपनियों के बढ़ते आकार और कारोबार को देखते हुए उनके लिए अपने सालाना लाभ का एक फीसद अंशदान अपने गिग वर्कर्स के पेंशन फंड में करना चाहिए।

श्रम मंत्रालय तथा EPFO अपने अध्ययन अनुमानों के आधार पर एग्रीगेटर कंपनियों से कहा भी है कि इस छोटे अंशदान से उन्हें ज्यादा फर्क नहीं आएगा, मगर गिग वर्कर्स को सेवानिवृत्ति के उपरांत मासिक पेंशन के तौर पर सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। कार्यक्षेत्र में स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा का फायदा वर्कर्स और कंपनियों दोनों को मिलेगा।

श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में इस समय गिग वर्कर्स की संख्या करीब एक करोड़ है, जो अगले पांच साल में पांच करोड़ तक पहुंच जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन वर्तमान सदस्यों के साथ इससे जुड़ने वाले नए युवाओं को सामाजिक सुरक्षा से जुड़े अपने योगदान को अपनी इच्छा अनुरूप बढ़ाने का विकल्प देने पर गंभीरता से गौर कर रहा है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय इसके लिए EPFO से जुड़े सुधारों को आगे बढ़ाने कर प्रक्रिया में जुट गया है। इस क्रम में EPFO पेंशन से जुड़ी जटिलताओं का सरलीकरण करने के साथ भविष्यनिधि तथा पेंशन फंड में योगदान को लचीला बनाने का एजेंडा अग्रिम पंक्ति में है। सूत्रों के अनुसार श्रम मंत्रालय कर्मचारियों के EPFO में 12 प्रतिशत योगदान की सीमा को बढ़ाने के पक्ष में है। इसमें कर्मचारी को अपनी इच्छा के अनुसार 12 प्रतिशत से अधिक योगदान देने की छूट देने का प्रस्ताव है।

हालांकि इसमें नियोक्ता के वर्तमान अंशदान की सीमा में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। कमर्चारी अंशदान सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव के पीछे मंत्रालय की मंशा यह है कि नौकरी ज्वाइन करने वाले युवा प्रारंभिक सालों में अपनी सामाजिक सुरक्षा के भविष्य की बेहतर प्लानिंग कर सकें तो सेवाकाल समाप्त करने के निकट आ रहे लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से अंशदान बढ़ाने की योजना बना सकें।

सितंबर तिमाही में क्यों सुस्त पड़ी भारत की रफ्तार, जानिए जीडीपी ग्रोथ घटने की वजह

India Q2 GDP Growth

सितंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 5.4 फीसदी रही। यह एक साल पहले की समान अवधि में 8.1 फीसदी थी। यहां तक कि मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भी जीडीपी ग्रोथ 6.7 फीसदी रही। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक कमजोर खपत और प्रमुख क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम जैसे कि बाढ़ की वजह से जीडीपी ग्रोथ में कमी आई है।

नई दिल्ली। भारत की तरक्की की रफ्तार वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में सुस्त पड़ गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 5.4 फीसदी रही। यह एक साल पहले की समान अवधि में 8.1 फीसदी थी। यहां तक कि मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भी जीडीपी ग्रोथ 6.7 फीसदी रही।
अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, कमजोर खपत और प्रमुख क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम, जैसे कि बाढ़, की वजह से जीडीपी ग्रोथ में कमी आई है।

आरबीआई के अनुमान से कम रही ग्रोथ

सितंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ एक्सपर्ट के अनुमान से काफी कम रही। इकोनॉमिक एक्सपर्ट पहले ही मानकर चल रहे थे कि दूसरी तिमाही में खपत घटने से जीडीपी ग्रोथ कम रहेगी। लेकिन, यह उनके अनुमान से भी कम रही। अधिकतर एक्सपर्ट 6 से 6.5 फीसदी जीडीपी ग्रोथ रहने का अनुमान जता रहे थे। आरबीआई ने 7 फीसदी ग्रोथ रहने का अनुमान जताया था। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के सर्वे में भी जीडीपी ग्रोथ 6.5 फीसदी रहने की उम्मीद जताई गई थी।

ग्रॉस वैल्यू एडेड में भी आई गिरावट

रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड (GVA) आर्थिक गतिविधियों को मापने वाले अहम पैमाना है। यह वित्त वर्ष 2024-25की दूसरी तिमाही में 5.6 फीसदी बढ़ा। पिछले साल की समान अवधि में यह 7.7 फीसदी था। इसका मतलब कि सालाना आधार दूसरी तिमाही में आर्थिक गतिविधियां सुस्त रहीं। नॉमिनल GVA ग्रोथ भी सालाना आधार 9.3 फीसदी के मुकाबले घटकर 8.1 फीसदी पर आ गई।

जीडीपी ग्रोथ सुस्त पड़ने की वजह क्या है?

आर्थिक जानकारों के मुताबिक, जीडीपी ग्रोथ सुस्त पड़ने की कई वजहें हैं। इसमें बढ़ती मंहगाई और ऊंची ब्याज दर अहम हैं। साथ ही, वेतन में भी उल्लेखनीय इजाफा नहीं हुआ, जिससे खपत को बढ़ावा मिला। यही वजह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने आरबीआई से अपील की है कि वह ब्याज दरों में कटौती करे। इससे कर्ज लेना सस्ता होगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

कंपनियों के कमजोर तिमाही नतीजे

कॉरपोरेट वर्ल्ड के सितंबर तिमाही काफी निराशाजनक रहे। देश की प्रमुख कंपनियों की जुलाई-सितंबर की अवधि में ग्रोथ पिछले चार वर्षों में सबसे खराब रही। इससे शेयर बाजार में भी बड़ा करेक्शन देखने को मिला। कंपनियों के कमजोर तिमाही नतीजों ने नए निवेश और व्यापार विस्तार योजनाओं को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। इस अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरे के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।

क्या जीडीपी ग्रोथ में आगे सुधार होगा

आर्थिक जानकार मौजूदा चुनौतियों के बावजूद दूसरी छमाही में जीडीपी ग्रोथ बेहतर रहने का अनुमान जता रहे हैं। RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी ग्रोथ 7.2 फीसदी रहने के अनुमान को बरकरार रखा है। हालांकि, यह पिछले वित्त वर्ष की 8.2 फीसदी ग्रोथ से काफी कम है। अगर केंद्रीय बैंक निकट भविष्य में ब्याज दरों में कटौती करता है, तो उससे खपत को बढ़ावा

चीन बन गया 'सोने की चिड़िया', खोज निकाला दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार

हुनान भूविज्ञान अकादमी ने स्वर्ण भंडार की खोज की है। यह भंडार पिंगजियांग काउंटी में है। यहां भूविज्ञानियों ने करीब तीन किलोमीटर की गहराई पर 40 स्वर्ण शिराओं की पहचान की है। तीन किलोमीटर की गहराई में एक हजार टन से ज्यादा सोना होने का अनुमान है। इसकी कीमत करीब 83 अरब डॉलर आंकी गई है। आइए जानते हैं कि चीन ने ये खदान कैसे खोज निकाली।

नई दिल्ली। चीन में दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है। हुनान प्रांत में मिले इस भंडार से एक हजार टन से ज्यादा सोना निकलने का अनुमान है। यह खदान धरती से करीब तीन किलोमीटर नीचे मिली है। इतना विशाल स्वर्ण भंडार मिलने से न सिर्फ चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि उसे अपनी घरेलू मांग को पूरा करने में मदद भी मिलेगी।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, हुनान भूविज्ञान अकादमी ने स्वर्ण भंडार की खोज की है। यह भंडार पिंगजियांग काउंटी में है, जहां भूविज्ञानियों ने करीब तीन किलोमीटर की गहराई पर 40 स्वर्ण शिराओं की पहचान की है। तीन किलोमीटर की गहराई में एक हजार टन से ज्यादा सोना होने का अनुमान है। इसकी कीमत करीब 83 अरब डॉलर आंकी गई है। यह संभवतः अब तक का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है। यह दक्षिण अफ्रीका की साउथ डीप खदान से भी बड़ा है। यहां लगभग 900 टन सोने का भंडार है।

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा के अनुसार, चीन दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक है। 2023 में दुनिया में कुल सोने के उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी दस प्रतिशत थी। इस वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में चीन ने 741 टन सोने की खपत की, जबकि उत्पादन 268 टन था। इसका मतलब यह हुआ कि उसे घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है।

यहां भी सोने का बड़ा भंडार

चीन की हुनान प्रांत से पहले दुनिया के बड़े भंडार दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, रूस, पापुआ न्यू गिनी, चिली, अमेरिका, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और डोमिनिकन गणराज्य सहित कई देशों में फैली खदानों में थे। साउथ डीप गोल्ड माइन, ग्रासबर्ग गोल्ड माइन और ओलंपियाडा गोल्ड माइन जैसी खदानें सोने के उत्पादन और भंडार में अग्रणी रही हैं।

भारत में सोने की बड़ी खदानें

भारत में अधिकांश सोने का भंडार कर्नाटक में है। यहां कोलार एहुट्टी और उटी की खदानों में भारी मात्रा में सोना निकाला जाता है। इनमें कोलार गोल्ड माइंस सबसे मशहूर है। सोने की इस खदान पर फिल्म भी बन चुकी है, जो बेहद सफल रही थी। कोलार गोल्ड फील्ड को 2001 में बंद कर दिया गया। इस खदान से 120 साल के इतिहास में 800 टन से अधिक सोना निकाला गया।

आरबीआई के पास कितना है स्वर्ण भंडार

पिछली कुछ तिमाहियों से दुनियाभर के देश अपना गोल्ड भंडार बढ़ा रहे हैं। इनमें भारत और चीन भी शामिल है। आरबीआई के पास सितंबर के आखिर में 855 टन गोल्ड रिजर्व था। इसकी वजह भू-राजनीतिक तनाव का बढ़ना है, जिसके चलते दुनियाभर के देश डॉलर पर अपनी निर्भरता घटाना चाहते हैं। इसका सबसे अच्छा विकल्प गोल्ड है, क्योंकि यह इसे सुरक्षित निवेश समझा जाता है। यह महंगाई के खिलाफ भी काफी कारगर हथियार के तौर पर काम करता है।

सोना हुआ सस्ता, चांदी की भी बढ़ी चमक; चेक करें लेटेस्ट प्राइस

नई दिल्ली। सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 700 रुपये बढ़कर 79,400 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाली कीमती धातु गुरुवार को 78,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई। चांदी भी 1,300 रुपये बढ़कर 92,200 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। गुरुवार को चांदी की कीमत 4,900 रुपये गिरकर 90,900 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई थी।

व्यापारियों का कहना है कि विदेशों में सकारात्मक रुख और घरेलू मांग में वृद्धि के कारण धारणा में तेजी आई। इससे मुख्य रूप से सोने की कीमतों में तेजी आई। इस बीच, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर वायदा कारोबार में दिसंबर डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध 602 रुपये या 0.79 प्रतिशत बढ़कर 76,326 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए।

एलकेपी सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी के वीपी रिसर्च एनालिस्ट जतिन त्रिवेदी ने कहा, ₹मौजूदा भू-राजनीतिक चिंताओं के बीच सुरक्षित निवेश की मांग के समर्थन से एमसीएक्स पर सोने में सकारात्मक कारोबार हुआ।₹ दिसंबर डिलीवरी वाले चांदी के अनुबंध 1,049 रुपये या 1.19 प्रतिशत बढ़कर 89,051 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए। वैश्विक स्तर पर, कॉमेक्स सोना वायदा 20.60 डॉलर प्रति औंस या 0.77 प्रतिशत बढ़कर 2,685.40 डॉलर प्रति औंस हो गया।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज में कमोडिटीज के सीनियर एनालिस्ट सौमिल गांधी ने कहा, "शुक्रवार को सोने में मामूली ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ तेजी आई। इसकी वजह सुरक्षित निवेश के लिए खरीदारी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा दिसंबर की बैठक में ब्याज दरों में कटौती जारी रखने की संभावना है।" एशियाई बाजार में चांदी भी 1.94 प्रतिशत बढ़कर 31.15 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।

मिराए एसेट शेयरखान के एसोसिएट वीपी, फंडामेंटल करेंसीज एंड कमोडिटीज प्रवीण सिंह ने कहा, ₹भू-राजनीतिक चिंताओं के कारण शुक्रवार को हाजिर सोने में लगातार चौथे दिन तेजी रही।₹ सिंह ने कहा कि गुरुवार को मिसाइल और ड्रोन हमलों के साथ यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाने के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि रूस यूक्रेन को परमाणु-सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बना सकता है। इससे कीमती धातु की ओर निवेश बढ़ा है।

38% महिलाएं बनीं सिविल सेवा अधिकारियों का हिस्सा: अमित शाह

इशिका मुख्य रिपोर्टर रांची झारखंड न्यूज परिवहन विशेष

देश की सिविल सेवाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने एक नया इतिहास रच दिया है।* केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 99वें फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह को संबोधित करते हुए बताया कि इस वर्ष के बैच में चयनित 38% अधिकारी महिलाएं हैं। यह आंकड़ा भारत में महिला सशक्तिकरण और 'महिला-प्रधान विकास' के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न की ओर एक अहम कदम है।

महिलाओं की भागीदारी नीति निर्माण की कुंजी

अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा, ₹जब तक देश की 50% आबादी, यानी महिलाएं, नीति निर्माण में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेंगी, तब तक 'महिला-प्रधान विकास' का सपना पूरा नहीं हो सकता।₹ उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि यह समाज में सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है।

आंकड़ों से नहीं, परिणामों से आता है विकास

शाह ने अधिकारियों से कहा कि सिविल सेवक केवल नीतियों का पालनकर्ता नहीं, बल्कि उनके क्रियान्वयन के मुख्य स्तंभ हैं। उन्होंने ज़िला मजिस्ट्रेट्स से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा का अधिकतम उपयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा, ₹आंकड़ों से विकास नहीं होता, बल्कि परिणामों से होता है। जब अधिकारी एआई और डेटा के सही उपयोग से निर्णय लेंगे, तो न केवल उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि समाज पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा।₹

सुरक्षा के क्षेत्र में भी महिला नेतृत्व आवश्यक

गृह मंत्री ने देश की चार प्रमुख चुनौतियों—आतंकवाद, नक्सलवाद, उत्तर-पूर्व का उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी—पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की सख्त नीतियों के कारण इन क्षेत्रों में पिछले 10 वर्षों में उल्लेखनीय सफलता मिली है। ₹महिला अधिकारी इन चुनौतियों का सामना करने में नए दृष्टिकोण और साहस के साथ आगे आ सकती हैं।

महिलाएं बदलाव की सूत्रधार हैं

अमित शाह ने कहा, ₹महिलाओं की भागीदारी किसी भी समाज की दिशा और दशा बदल सकती है। वे केवल प्रशासन की भागीदार नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव की सूत्रधार हैं। एक महिला अधिकारी का काम केवल कार्यालय तक सीमित नहीं होता, वह समाज को बेहतर बनाने में सक्रिय भूमिका निभाती है।

महिलाओं का बढ़ता कदम: सशक्त भारत की पहचान

आज, जब महिलाएं देश की सबसे चुनौतीपूर्ण सेवाओं में अपनी जगह बना रही हैं, यह संकेत है कि भारत में बदलाव हो रहा है। 38% महिलाओं का सिविल सेवाओं में चयन यह दर्शाता है कि जब महिलाओं को सही अवसर और मंच मिलता है, तो वे हर क्षेत्र में श्रेष्ठता साबित करती हैं।

यह उपलब्धि न केवल महिलाओं के लिए गर्व का विषय है, बल्कि देश के उज्ज्वल भविष्य का प्रमाण भी है।

जैसे-जैसे महिलाओं का कदम आगे बढ़ेगा, भारत का भविष्य और अधिक सशक्त होगा।*

इंडिगो एयरलाइंस का ऐलान: 1 जनवरी से उड़ान भरेगी 5 नई उड़ानें

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर : नए साल में भुवनेश्वर एयरपोर्ट से 5 नई फ्लाइटें उड़ान भरेगी। इंडिगो एयरलाइंस की ओर से यह सेवा 1 जनवरी से शुरू होने जा रही है, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से यह सेवा 3 जनवरी से शुरू होने जा रही है। इंडिगो सप्ताह में 4 बार भुवनेश्वर से इंदौर और 3 बार भुवनेश्वर से देहरादून तक उड़ान भरेगी।वहीं, भुवनेश्वर से लखनऊ और राजस्थान के जयपुर के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें सप्ताह में तीन बार संचालित होंगी। इसके साथ ही यह केरल के कोच्चि शहर के लिए भी सप्ताह में 7 दिन चलेगी।

अशांत सुंदरगढ़; कोइड़ा सेल ऑफिस के सामने हुआ रण भूमि

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर : सुंदरगढ़ जिला कोइड़ा माइनिंग मंडल सेल द्वारा संचालित तालडीही लौह अयस्क खदान पर धरना एवं विरोध प्रदर्शन। लौह अयस्क खदान को अगले 25 वर्षों के लिए अडानी को सौंपने का अनुबंध रद्द करने की मांग को लेकर सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जब विधायक और कुछ प्रदर्शनकारी चर्चा के लिए सेल कार्यालय जा रहे थे, तभी सीआईएसएफ बलों के हस्तक्षेप से स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गयी।कोइदा सेल कार्यालय पल्टिला रेंच के सामने 3 घंटे तक। धक्का, धक्का स्थिति उस समय बेकाबू हो गयी जब बन्नई विधायक लक्ष्मण मुंडा 15 सूत्री मांग पर चर्चा के लिए सेल कार्यालय जा रहे थे। मुख्य गेट से सेल में प्रवेश करते समय वहां तैनात सीआईएसएफ बलों ने विधायकों को धक्का दे दिया। विधायकों के साथ अन्य जन प्रतिनिधि और महिलाएं भी थीं। स्थिति बहुत ख़राब हो गयी थी।

सेल ऑफिस के सामने तीन घंटे तक मारपीट हुई। विधायक ने सीआईएसएफ बलों के खिलाफ हजारों की धनराशि जुटाई है। तालडीही लौह अयस्क खदान को 25 साल के लिए अडानी को देने के समझौते को रद्द करने, प्रभावित लोगों को रोजगार देने और खनन क्षेत्र के पर्यावरण में सुधार जैसी कुल 15 मांगों को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। सेल का निजीकरण न करने, अडानी से अनुबंध रद्द करने जैसी 15 सूत्री मांगों के समाधान के लिए वार्ता विफल हो गई है। कल से कोइड़ा माइनिंग सेल में खदानों और रेलवे साइडिंग से खनन और परिवहन पूरी तरह बंद रहेगा। चेतावनी दी गई है कि जब तक विधायकों और महिला प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने वाले सीआईएसएफ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक कोइड़ा खनन क्षेत्र के अंतर्गत सभी सेल खदानों में खनन बंद रहेगा।

मत लिखो गांधी, वाड्रा हो तुम,

अरे भई मत लिखो गांधी, वाड्रा हो तुम,
आपकी पार्टी भले चाहे जाए झूम झूम।
बाबा ने दिया बहना को राखी का गिफ्ट,
ये वायनाड में मिली है तभी उसे लिफ्ट!
लो प्रियंका हो गई लोकसभा में शिफ्ट।

अरे भई मत लिखो गांधी, वाड्रा हो तुम,
आपकी पार्टी भले चाहे जाए झूम झूम।
ये कहती हो मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ,
हां, मैं केरल से आगे भी बढ़ सकती हूँ!
मैं मम्मी को भी सरप्राइज दे सकती हूँ।

अरे भई मत लिखो गांधी, वाड्रा हो तुम,
आपकी पार्टी भले चाहे जाए झूम झूम।
मैं लू पार्टी को आगे बढ़ाने का संकल्प,
अगर सोनियाजी खोज रहीं है विकल्प!
हाँ, कोशिश करूंगी हो जाए कायाकल्प।

अरे भई मत लिखो गांधी, वाड्रा हो तुम,
आपकी पार्टी भले चाहे जाए झूम झूम।
राहुल बाबा आपने घुमाया खूब संविधान,
इतने सालों से पार्टी में न डाल सके जान!
भैया अब तो दे दो बहना के हाथ कमान।

संजय एम. तराणेकर

फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री करना चाहिए : वरिष्ठ समाजसेवी राजेश खुराना

फिल्म के माध्यम से गोधरा के वास्तविक सत्य को देश की जनता के सामने लाने का प्रयास सराहनीय : वरिष्ठ समाजसेवी राजेश खुराना

आगरा,संजय सागर सिंह। फिल्म 'द साबरमती रिपोर्ट' को देखने के बाद वरिष्ठ समाजसेवी राजेश खुराना ने इस फ़िल्म की प्रशंसा करते हुए कहा, ₹मैं साबरमती रिपोर्ट की पूरी टीम को बधाई देता हूं, जिन्होंने इस वास्तविक सत्य को देश की जनता के सामने फिल्म के माध्यम से लाने का प्रयास किया और इस फ़िल्म की पूरी टीम ने गोधरा के सच को सामने लाकर अपना राष्ट्रीय कर्तव्य निभाया। हमारा विनम्र निवेदन हैं कि फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को पुरे देश में टैक्स फ्री करना चाहिए।"

श्री खुराना ने कहा,₹गुजरात दंगों को सब जानते हैं, लेकिन गोधरा की सच्चाई से युवा और आम लोग परिचित नहीं हैं। अब यह फिल्म इस सच्चाई को उजागर कर रही है कि गोधरा में 69 श्रद्धालु कैसे मारे गए। यह एक बड़ा और सफल प्रयास है, जिसमें साबरमती रिपोर्ट की पूरी टीम और कलाकारों ने गोधरा के सच को सामने लाकर अपने राष्ट्रीय कर्तव्य को पूरा किया है।₹

राजेश खुराना ने आगे कहा, "यह फिल्म बताती है कि किन लोगों ने किस प्रकार षड्यंत्र रचा और ऐसे लोगों को देश के सामने लाना आवश्यक है। साबरमती ट्रेन में सवार श्रद्धालु अयोध्या से धार्मिक अनुष्ठान करके लौट रहे थे, और गोधरा स्टेशन पर उनके साथ जो हुआ, उस पर हमेशा पर्दा डाला गया। षड्यंत्र करने वाले लोग सच्चाई को छिपाने में जुटे रहे हैं।"

उन्होंने यह भी कहा, ₹देश में आज भी राजनीतिक स्वार्थ के लिए झूठ फैलाया जा रहा है। ऐसे लोग समाज और देश के हितकारी नहीं हो सकते। यह फिल्म उस समय आई है जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बन रहा है। फिल्म की घटना अयोध्या से जुड़ी है, और गोधरा के सत्य को सभी को जानना चाहिए। मैं चाहता हूं कि यह फिल्म अधिक से अधिक लोगों द्वारा देखी जाए, और इसे टैक्स फ्री किया जाए।"

राजेश खुराना ने अंत में कहा, ₹गुजरात के गोधरा स्टेशन के पास 27 फरवरी 2002 को एक एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे में आग लगाई गई थी, जिसमें 59 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकतर कारसेवक थे। इस घटना के बाद राज्य में व्यापक दंगे भड़क उठे थे। 'द साबरमती रिपोर्ट' फिल्म, गुजरात के 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड पर आधारित हिंदी फिल्म है।

स्वच्छ वातारण और स्वच्छ जल ही स्वस्थ जीवन है : डॉ हृदयेश कुमार

फरीदाबाद हरियाणा. सैक्टर 11 अखिल भारतीय मानव कल्याण ट्रस्ट के राष्ट्रीय कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ एमपी सिंह ने

स्वच्छ वातारण और स्वच्छ जल से स्वस्थ जीवनपर प्रकाश डालते हुए स्वच्छ वातारण के लिए अपनी चिंता जताई और इस विषय को गंभीरता से लेते हुए अपनी टीम के साथ विशेष रूप से विचार किया और कहा कि अभी भी समय है हम सभी लोगों को सिर्फ थोड़ा सा समय निकाल कर पेड़ पौधों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जिसमें हम सभी को पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधों को लगाना जरूरी है अगर हम सभी अभी तक नहीं समझ सकते हैं तो आने वाला समय बहुत ही भयानक होगा स्वच्छ वातारण नहीं होने से आज कल बहुत सी बीमारी हो रहीं हैं जिसमें आप को ऑक्सीजन के लिए ही हॉस्पिटल में बहुत अधिक भुगतान करना पड़ता है आज के समय में सिर्फ स्वच्छ वातारण और

स्वच्छ जल का सेवन करें तो आप को बहुत सी बीमारियों से निजात मिल सकती है इस लिऐ हम सभी लोगों से एक संकल्प की अपील करते हैं कि आप अपने किसी खास दिन जैसे जन्मदिन, शादी की सालगिरह या फिर कोई और पार्टी करते समय पर केवल एक पेड़ लगाना है

ट्रस्ट के संस्थापक डॉ हृदयेश कुमार ने बताया हमारे वातारण भी स्वच्छ होगा और जल भी इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए स्वच्छ जल का होना अत्यंत आवश्यक है। जिससे हानिकारक तत्वों, धूल, मिट्टी, बैक्टीरिया, वायरस और अन्य प्रदूषकों को हटाकर स्वच्छ जल प्रदान करता है।

अखिल भारतीय मानव कल्याण ट्रस्ट हमेशा स्वास्थ्य और समाज हित में अनेको तरह से आपकी सेवा में समर्पित रहेगा स्वच्छता से शरीर कीटाणुओं, बैक्टीरिया, और वायरस से लड़ पाता है. इससे संक्रमण का खतरा कम होता है और रोगों से बचाव में मदद मिलती है मानसिक स्वास्थ्य स्वच्छता से चिंता और तनाव कम होता है सामाजिक स्वास्थ्य स्वच्छता से व्यक्ति के रिश्तों में सभ्यता, सहानुभूति, ईमानदारी, और सभ्य व्यवहार बढ़ता है आत्मविश्वास स्वच्छ रहने से व्यक्ति को आत्मविश्वास मिलता है समय और धन की बचत

स्वच्छ रहने से कम बीमारियां होती हैं और बीमारियों के इलाज में होने वाला समय और खर्च भी बचता है.

स्वच्छ वातावरण के कुछ और फ़ायदे स्वच्छ वातावरण से पर्यावरण प्रदूषण से बचा जा सकता है.

स्वच्छ वातावरण से पानी अधिक स्वच्छ हो जाता है और पीने में अधिक आनंददायक हो जाता है स्वच्छ वातावरण से माहौल शांत रहता है स्वच्छ वातावरण से छात्रों की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ता है स्वच्छ वातावरण से सुरक्षा सुनिश्चित होती है खुद को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह स्वच्छ और शुद्ध रखने के लिए हम जो कुछ करते हैं, वो सब व्यक्तिगत स्वच्छता के तहत आता है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व और चरित्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यक्तिगत स्वच्छता में यह चीजें आवश्यक रूप से शामिल हैं शारीरिक स्वच्छताः नियमित स्नान, शरीर की साफ-सफाई का ध्यान रखना, स्वच्छ कपड़े पहनना, हाथ-मुंह धोना, समय पर नाखून-बाल काटना और दांतों की सफाई शामिल है। अच्छे और शुद्ध विचार मानसिक स्वच्छता के तहत आते हैं। सामाजिक स्वच्छता में व्यक्ति के संबंधों में सभ्यता, सहानुभूति, ईमानदारी और सभ्य व्यवहार को बढ़ावा दिया जाता है।

भारत की पहली लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल

यह मिसाइल की बहुमुखी प्रतिभा और सटीकता को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न गति और ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए जटिल युद्धाभ्यास करने में भी सक्षम है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल अत्याधुनिक एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर से लैस है जो इसके प्रदर्शन और विश्वसनीयता को बढ़ाता है। ये मिसाइलें आमतौर पर सबसोनिक होती हैं और इलाके से सटे उड़ान पथों का अनुसरण कर सकती हैं, जिससे उन्हें पता लगाना और रोकना कठिन हो जाता है, जिससे दुश्मन की रक्षा में भेदने में रणनीतिक लाभ मिलता है। इसे बेंगलुरु में डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित किया गया है, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल विभिन्न डीआरडीओ प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योगों के बीच सहयोग का परिणाम है। हैदराबाद में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) और बेंगलुरु में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने विकास-सह-उत्पादन भागीदार के रूप में काम किया। रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने पहले ही आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) प्रक्रिया के तहत स्वीकृत मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को मंजूरी दे दी थी। मिसाइल के सफल परीक्षण को भारत की रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है, खासकर लंबी दूरी के सटीक हमलों के क्षेत्र में।

-डॉ सत्यवान सौरभ

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने 12 नवंबर 2024 को अपनी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया। पहली उड़ान ओडिशा के तट पर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से एक मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर से उड़ाई गई। एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, बेंगलुरु द्वारा अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योगों के योगदान के साथ विकसित, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल आधुनिक सैन्य शस्त्रागार में एक महत्त्वपूर्ण अतिरिक्त है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को मोबाइल ग्राउंड-आधारित सिस्टम और फ्रंटलाइन जहाजों दोनों से लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो एक सार्वभौमिक वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल का उपयोग करता है, जो इसके परिचालन लचीलेपन को और बढ़ाता है। इसे मोबाइल ग्राउंड-आधारित सिस्टम और फ्रंटलाइन जहाजों दोनों से लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, एक सार्वभौमिक वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल का उपयोग करके, जो इसके परिचालन लचीलेपन को और बढ़ाता है। यह मिसाइल की बहुमुखी प्रतिभा और सटीकता को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न गति और ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए जटिल युद्धाभ्यास करने में भी सक्षम है।

लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल अत्याधुनिक एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर से लैस है जो इसके प्रदर्शन और विश्वसनीयता को बढ़ाता है। ये मिसाइलें आमतौर पर सबसोनिक होती हैं और इलाके से सटे उड़ान पथों का अनुसरण कर सकती हैं, जिससे उन्हें पता लगाना और रोकना मुश्किल हो जाता है, इस प्रकार दुश्मन की सुरक्षा में भेदने में रणनीतिक लाभ मिलता है। इसे बेंगलुरु में डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित किया गया है, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल विभिन्न डीआरडीओ प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योगों के बीच सहयोग का परिणाम है। रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने पहले एलआरएलएसीएम को एक मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में मंजूरी दी थी, जिसे स्वीकृति की आवश्यकता (एओएन) प्रक्रिया के तहत मंजूरी दी गई थी। मिसाइल के सफल परीक्षण को भारत की रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है, विशेष रूप से लंबी दूरी के सटीक हमलों के क्षेत्र में।

भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया। ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) में आयोजित पहला परीक्षण एक मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर से किया

गया और यह एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि मिसाइल ने योजना के अनुसार प्रदर्शन किया और सभी प्राथमिक मिशन लक्ष्यों को पूरा किया। परीक्षण के दौरान, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल पर रडार, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और इसके उड़ान पथ के साथ लगाए गए टेलीमेट्री उपकरण सहित सेंसर की एक सरणी का उपयोग करके बारीकी से निगरानी की गई थी। मिसाइल ने सटीक वेपॉइंट नेविगेशन का प्रदर्शन किया और अलग-अलग ऊंचाइयों और गति पर जटिल युद्धाभ्यास को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइलें आधुनिक सैन्य शस्त्रागार का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो रणनीतिक लक्ष्यों पर स्टैंड-ऑफ दूरी से लंबी दूरी के हमले करने में सक्षम बनाती हैं, जिसका अर्थ है कि मिसाइल को लक्ष्य से बहुत दूर लॉन्च किया जा सकता है, जिससे लॉन्च प्लेटफॉर्म और इसे संचालित करने वाले कर्मियों को नुक़सान से सुरक्षित रखा जा सकता है। ये मिसाइलें आमतौर पर सबसोनिक होती हैं और भूभाग से सटे उड़ान पथों का अनुसरण कर सकती हैं, जिससे उनका पता लगाना और अवरोधन करना कठिन हो जाता है, इस प्रकार दुश्मन की सुरक्षा को भेदने में रणनीतिक लाभ मिलता है।

लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के अन्य उदाहरणों में यूएस टॉमहॉक और रूस की कैलिबर शामिल हैं, दोनों ही सटीक, लंबी दूरी के हमलों में अपने उपयोग के लिए जाने जाते हैं। बेंगलुरु में डीआरडीओ के एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (ADE) द्वारा विकसित, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी परियोजना है। कुछ सेंसर और एक्सेलेरोमीटर को छोड़कर मिसाइल के सभी घटक स्थानीय रूप से सोर्स किए गए हैं। हैदराबाद में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) और बेंगलुरु में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने मिसाइल के एकीकरण और तैनाती में योगदान देते हुए विकास-सह-उत्पादन भागीदारों के रूप में सहयोग किया है। जमीन-आधारित और नौसैनिक तैनाती दोनों के लिए डिज़ाइन की गई, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल (UVLM) का उपयोग करके मोबाइल ग्राउंड प्लेटफ़ॉर्म और जहाजों से लॉन्च किया जा सकता है, यह एक सिस्टम है जिसे ब्रह्मोस एयरोस्पेस द्वारा पेटेंट किया गया है और यह पहले से ही 30 भारतीय नौसेना के जहाजों पर चालू है।

यह मिसाइल एक रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा स्वीकृत मिशन मोड प्रोजेक्ट है जो स्वीकृति की आवश्यकता (AoN) के तहत है, जो इसके रणनीतिक महत्त्व पर ज़ोर देता है। 1,000 किलोमीटर से अधिक की योजनाबद्ध सीमा के साथ, यह मिसाइल भारतीय सशस्त्र बलों, विशेष रूप से नौसेना को अपनी समुद्री-स्किमिंग क्षमताओं के साथ महत्त्वपूर्ण ताकत देगी। मिसाइल के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए लगभग 20 अतिरिक्त परीक्षण उड़ानों की योजना बनाई गई है, जिसमें स्वदेशी रेडियो-फ्रीक्वेंसी सीकर के माध्यम से टर्मिनल होमिंग भी शामिल है। सूत्रों के अनुसार, डीआरडीओ द्वारा मिसाइल के परीक्षण पूरे होने के बाद, भारतीय नौसेना लगभग 5,000 करोड़ रुपये की क़ीमत की लगभग 200 लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का ऑर्डर दे सकती है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा अनुमोदित, एओएन द्वारा स्वीकृत मिशन मोड परियोजना है, जिसके सेवा में प्रवेश के लिए एक निर्धारित समय-सीमा है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023